प्रतिवेदन शाखा

असंशोधित

1 8 JUL 2002

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग २—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर रहित)

बि० स० मु० (एल० ए०) 86--मोनो--1000--16-3-2002--,

द्वादश विधान-सभा
अष्टम - सत्र

बृहस्पतिवार, तिथि 18 जुलाई, 2002 ई0 / 27 आषाढ़, 1924 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के कई माननीय सदस्यगण नारेबाजी करते हुए सदन के वेल में आ गये)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अभी यह सब बात नहीं होगी, प्रश्नोत्तर काल अभी चलने दीजिए।

(इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के भी कई माननीय सदस्यगण नारेबाजी करते हुए सदन के वेल में आ गये)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति, यह बहुत गलत बात है। चाहे पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, यह अच्छी बात नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष (खड़े होकर) : शांति-शांति। कृपया आपलोग बैठ जाईए, शून्यकाल में इसको उठाइयेगा। अभी बैठिए न।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति-शांति । यदि आपलोग, पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यगण, विधान सभा की कार्यवाही को इस रूप में बाधित करते रहेंगे तो मुझे बाध्य होकर प्रश्नोत्तर-काल को स्थगित करना पड़ेगा ।

(व्यवधान)

(सदन के वेल में माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी जारी)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

......

अन्तराल के बाद ।

"(अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

सभा के समक्ष प्रतिवेदनों को रखा जाना

श्री अनुप लाल यादव:- अध्यक्ष महोदय, बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 211 (1) के तहत मैं प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति का 144 वां प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं ।

वित्तीय कार्य ।

अध्यक्ष:- माननीय सदस्य, श्री गणेश प्रसाद यादव अपना भाषण प्रारंभ कीजिए । पांच मिनट में आप समाप्त करें ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव:- अध्यक्ष महोदय, मैं अपने डेरे से चला तो सोचा मंत्रिमंडल सचिवालय पर बहस है तो रास्ते में मंत्रालय को खोजने लगा, कहीं मुझे मंत्रालय नहीं मिला, सचिवालय जरूर मिला । मंत्रिमंडल सचिवालय पर बहस है, पर यहां मंत्रालय नहीं है, सचिवालय है, सरकार जवाब दे तो - - -

अध्यक्ष:- आप स्वयं विद्यमान हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, सारी बातों की जानकारी आपको है ।

श्री अब्दुल जलील मस्तान :- अध्यक्ष महोदय, आज पूरे बिहार के मदरसे के टीचर - - -

अध्यक्ष:- आपको इस विषय पर विधिवत् बुलवायेंगे, अभी बैठिये ।

श्री गणेश प्रसाद यादव:- महोदय, मैं कह रहा था कि जिस ढंग से पढ़ने वाले लड़कों की संख्या बढ़ी है, कालेजों में नामांकन करने के लिए सीट नहीं बढ़ाये गये हैं । 25-30 वर्षों से जिन विभागों में और जिन महाविद्यालयों में, जिन इन्जीनियरिंग कालेजों में, जिन मेडिकल कालेजों में छात्रों के नामांकन के लिए जो सीट निर्धारित की गयी थी आज भी उतना ही निर्धारित है । एक तरफ साक्षरता बढ़ाने के

लिए ,लोगों को पढ़ाने के लिए सरकार बल देती है और दूसरी तरफ जो स्थापित संस्थायें हैं ,उन संस्थाओं में भी सीट नहीं बढ़ा रही है । महोदय,इस सरकार में कोई संकल्प शक्ति नहीं है ,अगर इस सरकार में संकल्प शक्ति होती तो हर विधायक दल की बैठक में दल को मजबूत करने और मुख्य मंत्री की ताकत को मजबूत करने के लिए संकल्प दुहराया नहीं जाता ,निर्णय नहीं लिया जाता ,इसलिए इस सरकार में संकल्प शक्ति नहीं है जिसके कारण यह सरकार बदले की भावना से कार्रवाई करती है । महोदय आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देश के जाने माने नेता और भारत सरकार के मंत्री श्री शरद यादव पर मधेपुरा की पुलिस 500/-रू0 और घड़ी छीनने के आरोप में आरोप पत्र दाखिल किया है ,उन्हें चार्जसीटेड किया है । अब इससे अधिक बदले की भावना से सरकार काम करने का कार्रवाई करती है ,इससे और क्या कहा जा सकता है ।

(इस अवसर पर मा0स0श्री अनुप लाल यादव ने आसन ग्रहण किया)

महोदय ,आज नोकरशाही थैलाशाही नेताशाही तीनों का तिकोन बन गया है । डा0 लोहिया कहा करते थे कि दो ही आफत का जड़ है और यहां तीनों का तिकोन बन गया है और कोई भी बातें ये तीनो मिल जुल कर करते हैं ,किसी घटना को अंजाम देने का । इन घटनाओं को अंजाम इस तिकोण के माध्यम से मिलजुल कर जो इनका तिकोण है ,इस तिकोण से काम चलाते हैं । आज सम्पूर्ण बिहार में अराजकता की स्थिति है ,कहीं कोई कानून,प्रशासन और न्याय का राज्य नहीं चल रहा है । एक तरफ सरकार यह कहती है ,जब इसी विधान सभा में प्रश्न लिये जाते हैं विकास के नाम पर सड़क बनाने के लिए तो सरकार कहती है आर्थिक अभाव की , इस वित्तीय वर्ष में नहीं होगा अगले वित्तीय वर्ष में नहीं होगा ,जब आपकी माली हालत इतनी खराब है तो इतना भारी भरकम मंत्रिमंडल रखने का क्या दरकार है । क्रमशः

टर्न-3/ज्योति/18-7-2002

क्रमशः

श्री गणेश प्रसाद यादव : आप अपने मंत्रिमंडल के आकार को छोटा करिये, खर्च को कम करिये, जहाँ फिजूलखर्ची नजर आए संसाधन जुटाने के लिए, संसाधन बचाने के लिए आप फिजूलखर्ची को बंद करिये लेकिन आप फिजूलखर्ची घटा नहीं रहे हैं, फिजूलखर्ची बढ़ते जा रहा है। कल एक माननीय सदस्य बोल रहे थे हमको मैन्डेट मिला है चुनाव में। आपको चुनाव में मैन्डेट मिला है कि पार्टी तोड़ने का मैन्डेट मिला है। और यह आपको हर समय मिला रहता है। आप बसपा के चार आदमी को ले गए। यह मैन्डेट तो नहीं मिला था और फिर इधर दूसरे दलों को भी फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यह मैन्डेट तो जनता ने नहीं दिया है। जनता तो एकबार आपको चुनाव में मैन्डेट दे दिया लेकिन हर बार नया नया मैन्डेट का इजाद करते रहते हैं यह किसी भी अच्छी सरकार के लिए और समाज के लिए राज्य चलानके के लिए जिस प्रवृति को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिस प्रवृति को आप बढ़ावा दे रहे हैं यह प्रवृति आज न कल खतरे की घंटी के रूप में सामने आ जायेगी। महोदय, इस सरकार को अदृश्य शक्ति चला रही है। जैसे लोग कहते हैं कि प्रकृति को चलाने वाली शक्ति अदृश्य है, उसका न रूप है न रंग है उसीतरह से इस सरकार को एक अदृश्य शक्ति चला रही है। और जैसे एक अदृश्य शक्ति एक हाथ में होगी तो उस सरकार की कोई अच्छी बात बनने लायक नहीं रहेगी। पिछली बार इसी सदन में जब बिहार का बंटवारा हुआ तो सदन में नहीं, सदन के बाहर देखने में आया कि बिहार में चंदन का वृक्ष लगेगा 200 एकड़ में चंदन का बाग लगायेंगे। इससे मेरे जैसा आदमी उत्साहित हो गया। अन्य चीजों से बिहार की गरीबी दूर नहीं कर सकते हैं लेकिन चंदन का वन लगने के बाद बिहार की गरीबी दूर हो जायेगी। जब एक वन विभाग के बड़े पदाधिकारी से मेरी बातचीत हुई तो कहा समतल भूमि में तो वन लगता ही नहीं है कम से कम वन लगानके केलिए 2 हजार फीट की ऊँचाई की जमीन चाहिए। इस तरीके से एक काल्पनिक बात कह कर पूरे राज्य के विकास को रोकने का प्रयास है कुछ लोगों के द्वारा, जो सरकारी पैसे हैं उस पैसे को घेर के और जिन कार्यों के लिए ये पैसे आए हैं उसमें नहीं लगने देना सबसे बड़ी महोदय आर इस सरकार और इस राज्य के लिए कोई चीज है तो यह सरकारी एजेन्ट खड़ा करते हैं। कोई भी प्रखंड नहीं है जहाँ इनके बिचौलिए के द्वारा

सरकारी पैसे का बंदरबाट नहीं होता है । ऊपर से चाहे जो तड़क भड़क दे दें लेकिन जो वास्तविक स्वरूप है वह गांव के विकास में देखिये । कल एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि 10 लाख इन्दिरा आवास बनाया गया । छोड़ दीजिये दो लाख झारखंड में चला गया । 10 लाख बनाया 10 वर्षों में 37 जिलों में । एक जिले में पड़ा दो हजार कम से कम एक प्रखंड में 10-12 पंचायत पड़ता है ।एक पंचायत में अगर 10-15 यानी । सौ से अधिक आप एक पंचायत में नहीं बना पाए हैं और इसमें भी आप अपनी पीठ थपथपाते हैं । इसमें आपका क्या योगदान है ? यह पैसा भारत सरकार का है इसमें 20 प्रतिशत की आपकी उपलब्धि होगी क्योंकि अगर इसमें । सौ रुपया खर्च होता है इसमें 20 रुपया आपकी उपलब्धि मानी जायेगी और 80 रुपये की उपलब्धि आपकी नहीं है और आप कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं । 33 सौ किलोमीटर सड़के चली गयीं एन0एच0 में और आपके पास जो सड़क की लायबिलटीज थी उसमें से 33 सौ कि0मी0 को भारत सरकार ने अपने लायबिलटी में ले लिया । आपके पास सड़कों की लम्बाई कम हो गयी तो रख रखाव अच्छा होना चाहिए लेकिन उसका भी रख रखाव ठीक नहीं है । आप स्वास्थ्य विभाग की बात करते हैं कि हम बहुत सुधार कर रहे हैं और हर लोगों के स्वास्थ्य अच्छा रखने की बात आप करते हैं । छोड़ दीजिये दूसरी जगह चले जाईये पी0एम0 सी0एच0 में । जो आम आदमी है, गरीब आदमी है उसका पी0एम0सी0एच0 में क्या हालत है । गांव के दूर दराज के अस्पतालों की क्या हालत है । डौक्टरों को भेजा जा रहा है बाढ़ के इलाके में, दूर दराज के गांवों में भेजते हैं लेकिन डौक्टर आपके हुकुम को नहीं मानते हैं, वर्षों वर्ष डौक्टर वहाँ नहीं जाते हैं । गांव का आदमी जहाँ बाढ़ आती है डूबा रहता है जिसको 5-7 घंटा नाव पर चढ़ना पड़ता है, किसी शहर के अस्पताल से सम्पर्क स्थापित होने के पहले ही उसके प्राण पखेरू उड़ जाते हैं । इसलिए आप अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत करिये । अदृश्य हाथों से अलग होईये ।इन चीजों पर ध्यान देकर ठीक ढंग से सरकार चलाईये । पिछली बार अखबारों में आपका बयान आया कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिहार में 4 मुख्यमंत्री हैं, चार की जगह तीन मुख्यमंत्री है एक औफिशियल और दो नौन औफिशियल । राज्य

सत्ता को केन्द्रीत कर अपनी पास रखिये । माननीय सदस्य नरेन्द्र सिंह जोये लोग बतला रहे थे कि इधर पढ़िये उधर पढ़िये लेकिन सदन में जो सामने लिखा हुआ है उसको नहीं पढ़ते हैं और बदले की भावना से काम करते हैं जो आपके खिलाफ खड़ा होता है । 5 सौ रूपया और घड़ी छिनने का आरोप लगाते हैं और हमारे नेता शरद यादव जी पर चार्ज शीट करवाते हैं जिसने शरद यादव जी पर पाँच सौ रूपया और घड़ी छिनने का चार्ज शीट किया है उसपर आपकार्रवाई करिये औरयदि ऐसे ही बदले की भावना से आप काम करियेगा तो आने वाले समय में आप जब इधर रहियेगा [illegible] तो आने वाली पीढ़ी आपसे यही व्यवहार करेगी । ।

सभापति (श्री अनुपलाल यादव): माननीय सदस्य, आप कल भी बोलें, आज भी बोलें। बोलने का समय निर्धारित है। अपना भाषण कन्क्लुड करें समाप्त समाप्त करें।

श्री गणेश प्रसाद यादव: कन्क्लुड करता हूं महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि अपने हृदय को विशाल कीजिये, जब हृदय विशाल होगा तो अच्छी सरकार बन पायेगी। तंगदिल आदमी नहीं अच्छी सरकार चला सकता है और न अच्छा प्रशासन दे सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अब्दुल जलील मस्तान: सभापति महोदय, कल से पूरे बिहार के मदरसा शिक्षक लोग विधान सभा के बाहर धरने पर बैठे हैं। संस्कृत शिक्षक भी हैं। उनका कहना है कि हमको 9 महीने का वेतन मिला है। 2000 में 8 महीने का और 2001 में 8 महीनें और 13 महीने का मुशहरा बाकी है। महोदय, सरकार ने वादा किया था कि जो एरियर बनता है वह दे देंगे जिसको आज तक नहीं दिया गया है। इसलिए सरकार से वे लोग अपना बकाया मांगने के लिए विधान सभा के बाहर खड़े हैं। इसी तरह से उनका कहना है कि सरकार ने घोषणा किया था कि 25। प्रतिशत डी०ए० ~~xxx~~ मदरसा शिक्षकों को देंगे जो आज तक उसका भी इम्पलीमेंटेशन नहीं हो पाया है। उसी तरह से महोदय सरकार ने पिछले विधान सभा में घोषणा किया था कि मदरसा शिक्षकों को मंथली भुगतान करेंगे वह भी आज तक नहीं हो पाया है। सारे गरीब लोग है और [illegible] भूख से तिलमिला कर विधान सभा के बाहर धरने पर बैठे हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार उनसे मिलकर उनकी मांगों का इम्पलीमेंटेशन कर दे, यही हमारी सरकार से गुजारिश है।

टर्न-5/राजेश/18.7.2002

श्री ललित कुमार यादव:- सभापति महोदय, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, संसदीय कार्य, विधान मंडल एवं निर्वाचन विभाग का जो बजट सरकार के द्वारा पेश किया गयाहै, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सभापति महोदय, हमलोग उत्तर बिहार से आते हैं और वहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आता है और हमलोगों का इलाका बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन केन्द्र की सरकार के द्वारा उपेक्षा बिहार के साथ किया जाता है। महोदय, प्रतिवर्ष उत्तर बिहार में बाढ़ आता है और केन्द्र सरकार से बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए जो राशि मिलनी चाहिए, नहीं मिलती है। दूसरे प्रदेशों में जब बाढ़ आता है, तो वहाँ पर पैकेज के रूप में ज्यादा राशि मिलता है और बिहार में बहुत ही कम मिलता है, यह केन्द्र सरकार की दुरंगी नीति है। महोदय, बाढ़ पर केन्द्र सरकार को ठोस पहल करना चाहिए, बाढ़ के संबंध में नेपाल की सरकारसे वार्ता करके, खासकरके उत्तर बिहार की स्थिति को सुधारने के लिए ठोस पहल करना चाहिए।

सभापति महोदय, आज बिहार राज्य में 22 वर्षों के बाद पंचायत का चुनाव हुआ है और यह इतना सफलतापूर्वक चुनाव यहाँ हुआ कि आज इस राज्य के लोग के द्वारा कह जाता था कि इस राज्य में चुनाव हो ही नहीं सकता है, लेकिन सभापति महोदय, आपको जानकर खुशी होगी कि राज्य सरकार की तत्परता से इस राज्य में पंचायत का चुनाव हुआ, सारे दलित, पिछड़े लोग, जितनी संख्या में जीतकर आये, वह राज्य को लिए खुशी की बात है। सभापति महोदय, इस राज्य का बँटवारा हुआ और बँटवारा इसलिए किया गया कि इस राज्य की स्थिति और बिगड़ जाय और यह केन्द्र सरकार की दुरंगी नीति के कारण इस राज्य का बँटवारा हुआ। सभापति महोदय, केन्द्र सरकार ने जान-बूझकर इस राज्यको बँटवाने का काम किया, चूंकि यहाँ आर0जे0डी0की सरकार है और आर0जे0डी0 की सरकार को बदनाम करने के लिए ही इस राज्य का बँटवारा किया गया। सभापति महोदय, यहाँ का जो रिसोंसेज था, वह निश्चित रूप से झारखंड राज्य में उससे ज्यादा हिस्सा चला गयाहै। राज्य के बँटवारे के बाद की जो आर्थिक स्थिति और जिस स्थिति से राज्य चल रहा है, निश्चित रूप से अपने रिसोंसेज से प्रगति की ओर है। सभापति महोदय, हमलोगों को लग रहा था, दूसरे लोगों को भी लग रहा था, हमारे विरोधी साथियों को भी लग रहा था कि राज्य के बँटवारे के बाद, इस राज्य की स्थिति में कहीं कोई, न सड़क बन पायेगा, न किसी को वेतन मिल पायेगा, लेकिन इसके बावजूद हमारे माननीया मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के नेतृत्व में, जो सरकार चल रही है।

क्रमशः

श्री ललित कुमार यादव ः क्रमशः ः विकास का काम हो रहा है । आज पुल-पुलिया भी काफी संख्या में बना है, सड़क का निर्माण भी हुआ है और जो पठन-पाठन का काम है, उसमें भी सुधार हुआ है । आज गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग, जो 1996 का आंकड़ा था, की आंकड़ा में कमी आयी है ।

आप बिहार राज्य को लीजिये । इस प्रदेश में आज अमन-चैन है । आप दूसरे प्रदेश को लीजिये जहां विरोधी पक्ष की सरकार है । आप गुजरात को देखिये । आज गुजरात धू-धू कर जल रही है । गुजरात ,जहां आपकी सरकार है, धू-धू कर जल रही है और बिहार निश्चित रूप से आपलोगों द्वारा लाख बदनाम करने, लाख प्रयास करने के बावजूद बिहार में आपका दाल गलने वाला नहीं है । बिहार में निश्चित रूप से अमन-चैन है । आंध्र प्रदेश को ले लीजिये । वहां निश्चित रूप से अमन चैन है । आंकड़े नीचे आये हैं । आप बिहार राज्य के साथ दुरंगी नीति अपना रहे हैं । केन्द्र सरकार बिहार के साथ दुरंगी नीति कर रही है, उसके बावजूद भी बिहार को कोई फर्क पड़नेवाला नहीं है । बिहार की सरकार अच्छी तरह से चल रही है और चलती रहेगी । केन्द्र सरकार से जो हिस्सा बिहार सरकार को मिलना चाहिए, वह नहीं मिलने के बावजूद भी अपने संसाधन पर सरकार अच्छी तरीके से चल रही है ।

सभापति महोदय, जब भी बिहार में बाढ़ आयी है, केन्द्र से पैकेज/रिलीफ के नाम पर कुछ नहीं मिला है और जहां बाढ़ नहीं आती है, वहां पैकेज मिलता है । लेकिन बिहार को पैकेज नहीं मिलता है ।

सभापतिः श्री अनूप लाल यादवः ः माननीय सदस्य, आप अपनी बातें जारी रखिये ।

श्री ललित कुमार यादवः माननीय सदस्य श्री नन्द किशोर यादव जी बोल रहे थे कि प्रखंड बना, अनुमंडल बना लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ । हम कहना चाहते हैं कि जहां भी प्रखंड बने, अनुमंडल बने, आज देख लीजिये, वहां पर विकास की क्या गति है ? वहां लोगों में खुशी है । लोगों में इतनी खुशी है कि वहां विकास हुआ है । जहां रोड बना है, वहां निश्चित रूप से खुशहाली ज्यादा आयी है । वहां के गरीब-गुरबा के मनोबल बढ़े हैं ।

सभापति महोदय, राज्य के बंटवारे के बाद लोग कहा करते थे कि यहां बालू और आलू बच गया है लेकिन सरकार अपने संसाधन का निरंतर विकास कर आगे बढ़ती जा रही है । ः क्रमशः ः

श्री ललित कुमार यादव (क्रमश:) - माननीय विधायकों को उनकी अनुशंसाओं पर उनके क्षेत्र में योजनाओं को कार्यान्वित कराने के लिए एक-एक करोड़ रुपये की राशि दी गई है। इस राशि से सभी माननीय सदस्यगण अपने-अपने क्षेत्र में जनहित में अनेक योजनाओं का कार्यान्वयन करा रहे हैं।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, केशरी जी। आप ध्यान से सुनने का काम करें। आपलोगों का जलन स्वाभाविक है। लाख प्रयास कर लें, इस राज्य में आप लोगों का दाल गलनेवाला नहीं है। महोदय, जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी इस राज्य के मुख्यमंत्री बने, जब से राजद की सरकार इस राज्य में आई, इन्हें छटपटाहट हो गई है। आप लाख छटपटाते रहें, केन्द्र सरकार छटपटाती रह जायेगी, बिहार की सरकार बिहार के विकास में अपना काम करती रहेगी। महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राज्य में विकास कार्य निरंतर गति से चल रहा है। विधायक फंड से विकास कार्य चल रहे हैं। 22 वर्षों के बाद, इस राज्य में पंचायतों के चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न हुये। इसके लिए माननीया मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं माननीया मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि बिना किसी हिंसा के इस राज्य में चुनाव पंचायत-चुनाव सम्पन्न हुये। इसी प्रकार नगर-निकायों के चुनाव भी सफलतापूर्वक हुये। आज राज्य में गरीबी-रेखा से नीचे गुजर-बसर करनेवाले लोगों की संख्या में कमी आई है। गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर

करने वाले लोगों को सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मदद कर रही है।

महोदय, बिजली के संबंध में कहना चाहता हूँ कि सरकार के प्रयास से इस में काफी प्रगति हुई है। गांवों में विद्युतीकरण का कार्य कराये जा रहे हैं।

सभापति [श्री अनुप लाल यादव] - माननीय सदस्य, आप अपनी बात समाप्त करें।

~~सभापति~~

श्री ललित कुमार यादव - महोदय, प्रखंड विकास पदाधिकारी, गया चार वर्षों से पदस्थापित हैं। इनके ऊपर भ्रष्टाचार का मामला कार्मिक विभाग में लंबित है जिसे तुरंत निष्पादित किया जाय। यह मेरा आपके माध्यम से आग्रह है।

सभापति (श्री अनूप लाल यादव) : माननीय सदस्य, श्री ललित कुमार यादव जी, आप आसन ग्रहण करें, आपका समय समाप्त हो गया । अब माननीय सदस्य, श्री उमा शंकर सिंह बोलेंगे ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, केन्द्र में साम्प्रदायिक सरकार है और बिहार में धर्मनिरपेक्ष सरकार है । गुजरात में आज स्थिति इनलोगों ने यह बना दी है कि सारे व्यापारी वहाँ से भाग कर दूसरे प्रदेश में पलायन कर रहे हैं लेकिन आज बिहार में अमन-चैन है । गुजरात में जो "सूरत" शहर है, इसका इनलोगों ने सूरत बिगाड़ दिया है । बिहार में जो धर्म निरपेक्ष सरकार है, यह सरकार रहेगी और अच्छी तरह से काम करती रहेगी । अब इनलोगों के पास कोई काम नहीं बचा है तो रथ लेकर निकलना चाहते हैं.....

सभापति (श्री अनूप लाल यादव) : माननीय सदस्य, आप आसन ग्रहण करें ।

श्री ललित कुमार यादव : ये लोग रथ निकालना चाहते हैं लेकिन आपका रथ चलने वाला नहीं है, आपके रथ का चक्का टूटने वाला है । आपलोग गुजरात से भी जाने वाले हैं । वहाँ चुनाव होने वाला है, चुनाव में आपकी पार्टी का खात्मा हो जायेगा । बिहार में आज गरीबों और दलितों की सरकार है तो इनलोगों को जलन हो रही है, घबराहट हो रही है । आज बिहार के गरीब और दलित का इस सरकार के शासनकाल में विकास हुआ है और बिहार में आज गरीब और दलित अपने अधिकार को समझने लगे हैं । आपलोग बिहार में कुर्सी के लिए टकटकी लगाकर ताकते रहियेगा लेकिन आपको कुर्सी मिलने वाला नहीं है । महोदय, बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद और माननीया राबड़ी देवी के नेतृत्व में यह सरकार चलती रहेगी ।

सभापति (श्री अनूप लाल यादव) : माननीय सदस्य, श्री ललित कुमार यादव जी, अब आपका भाषण समाप्त हो गया है, आप आसन ग्रहण करें । अब माननीय सदस्य, श्री उमा शंकर सिंह बोलेंगे । आप आसन की बात मानिये और बैठ जाइये ।

श्री ललित कुमार यादव : अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज दिल्ली की सरकार हिल रही है और यह सरकार जाने वाली है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ । धन्यवाद ।

श्री उमाशंकर सिंह : सभापति महोदय, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार, संसदीय कार्य, विधान मंडल एवं निर्वाचन विभाग पर जो कटौती प्रस्ताव आये हैं, उसके पक्ष में हम बोलने के लिए खड़े हुए हैं । लेकिन यह समझ में नहीं बात आती है कि किसपर बोलें, क्या कहें ? न मुख्य सचिव बैठे हैं और न ही डी०जी०पी० बैठे हैं, कौन यह बात सुनेंगे , कौन इम्पलीमेंट करेंगे ? यह बात समझ में नहीं आती है ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री अनूप लाल यादव) : माननीय मंत्रिगण बैठे हुये हैं, वे सुन रहे हैं ।

श्री उमा शंकर सिंह : डी०जी०पी० वर्दी में रहते हैं तो दिखाई देते हैं । रही बात सरकार की तो सरकार का आज नजारा देखा । सरकार पर्चा लेकर फहरा रही थी कि गिरफ्तार करो । अगर कोई मुजरिम है तो सरकार को गिरफ्तार करना चाहिये । सरकार किससे माँग कर रही थी, पेपर से, दीवाल से या लॉबी से माँग कर रहे थे । यह बात समझ में नहीं आती है । सरकार आज खुद ही कह रही है कि गिरफ्तार करो । सरकार यदि समझती है कि मुजरिम है तो गिरफ्तार कर लीजिये ।

कहने का मतलब यह है सभापति महोदय, कि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, संसदीय कार्य एवं अन्य विभागों का जो सवाल है तो इस राज्य में जो हत्यायें हो रहे हैं, बलात्कार की घटनायें हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, इसलिए पहले विधि-व्यवस्था से ही शुरू करता हूँ ।

महोदय, 55,938 लोगों की हत्यायें हुई हैं । अगर आपकी अनुमति होगी, समय यदि बढ़ायेंगे तो वर्षवार सूची , संख्या और आँकड़ा देंगे, सरकार का ही आँकड़ा है । महोदय, जितनी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उसी तरह की वृद्धि अपराध, हत्या और बलात्कार की घटनाओं में हो रही है । इसमें कहीं कोई कमी नहीं हो रही है, चाहे वह अपहरण की बात हो या और कोई घटना हो, मेरे पास वर्षवार आँकड़े हैं । चाहे महिलाओं के साथ अत्याचार, दुराचार और बलात्कार की बात हो, प्रत्येक वर्ष उसकी संख्या बढ़ती जा रही है ।

महोदय, यदि सरकार की मंशा ठीक हो तो कोई बात हो । सरकार कहती है कि ऑपरेशन खोज अभियान चलायेंगे लेकिन पुलिस को अपराधियों से मुकाबला करने के मुताबिक आधुनिक हथियार भी नहीं है ।

(क्रमशः)

टर्न:9:अंजना:दि० 18.7.02

...क्रमशः...

श्री उमाशंकर सिंह : थाने में गाड़ी की कमी है, साधन की कमी है तो साधनविहीन पुलिस क्या कर सकती है ? महोदय, डी०जी०पी० को कोई बात कहिए लेकिन वह समझता बहुत कम है। मैं जहाँ से आता हूँ, वहाँ एक अनुमंडल आरक्षी पदाधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद थे जिनको दिनांक 21.5.2001 को सेवानिवृत होना था लेकिन जब मैंने माह सितम्बर में पत्र लिखा तब मुख्यालय से आदेश गया और तब उनको दिनांक 21.9.2001 को रिटायर कराया गया । यह बात इसलिए उठी कि इन्होंने सरकार के चार माह का अतिरिक्त भुगतान, टी०ए०, डी०एस० ले लिया जो सैकड़ों केसों का, जैसा कि माननीय सदस्य श्री सत्यदेव सिंह जी ने जो मामला उठाया था और माननीय मंत्री श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा जी ने कहा था कि हम इसकी जाँच करायेंगे, सैकड़ों केसों का जो इन्होंने पर्यवेक्षण किया उसमें जनता से लाखों रुपया ऐंठा...

(व्यवधान)

आप बीच में क्यों टोक रहे हैं, आप सुनिए तो। हमें बोलने दिया जाय । उसके लिए हमने पत्र दिया । डी०जी०पी० ने कहा कि हम असमर्थ हैं। चूँकि गजेटेड ऑफिसर के सर्विस की बात है। तब उनको रिटायर कराया गया चार माह बाद । महोदय, पुलिस विभाग में यही होता है कि किसी मुजरिम को बिना गिरफ्तार किए और बिना जमानत लिए जिसपर दो-दो महीना से, तीन-तीन महीना से 307 का एवं कई दफा का वारंट है, इसके अनुमंडल पदाधिकारी श्री विजय कुमार थे, जिनका आज एस०टी०एफ० में हो गया, देख लें, ऐसे भी पर्यवेक्षण करनेवाले हैं, कहने का मतलब यह है कि कोई नियम-कानून से नहीं चल रहा है।

(व्यवधान)

ऑपरेशन खोज अभियान के बारे में जो कहा गया उसके संबंध में सरकार पुलिस को साधन मुहैया कराये, तभी होगा । राज्य के खराब विधि व्यवस्था के चलते लोग पलायन कर रहे हैं। गरीब तबके के लोग इस राज्य से पलायन कर रहे हैं।

महोदय, कारण क्या है ? उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। राज्य बँटने के बाद के बिहार कृषि पर आधारित है। गरीबों को मजदूरी नहीं मिलता है जिसके चलते अपने भूख मिटाने के लिए राज्य के बाहर हरियाणा, पंजाब, गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य में जा रहे हैं और वे गरीब मजदूर उन राज्यों का निर्माण कर रहे हैं लेकिन इस राज्य के निर्माण करने में उन्हें अवसर प्राप्त नहीं होता है। गरीब तबके के लोग पलायन कर रहे हैं अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए और अमीर तबके के लोग पलायन कर रहे हैं अपनी सम्पत्ति को बचाने के लिए। महोदय, दोनों तरफ से पलायन हो रहा है। सरकार को इसपर चिंतन करना चाहिए। आज हम आरक्षण देंगे तो कल वे आरक्षण देंगे, सरकार का चिंतन नहीं होगा तो पलायन इसी तरह से होते रहेगा, न रोजगार चलेगा और न रोजगार मिलेगा। जिसको रोजगार नहीं मिलता है वह रोजगार के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए जा रहा है और जो रोजगार वाले हैं वे अपनी सम्पत्ति को बचाने के लिए पलायन कर रहा है। इसके लिए सरकार को कृषि को प्राथमिकता देनी चाहिए, कृषि को उद्योग का दर्जा देना चाहिए, सरकार इसपर चिंतन करे। आजतक इतने दिनों में इस सरकार ने एक भी नकली दवाओं को बेचनेवाले पर, एक भी नकली खाद बेचनेवाले पर या नकली दवा / खाद बनाने वालों पर जांच कर कार्रवाई नहीं किया, मुकदमा नहीं किया। किसान अपने कमाई के ... बल पर उपज को बढ़ाता है...

(व्यवधान)

क्या आप बैठे-बैठे बोल रहे हैं, पुराने सदस्य हैं उनकी बात सुनिए, बोलिए।

सभापति श्री भूलाल यादव : माननीय सदस्य जो बैठे-बैठे बोलते हैं, उनका आप नोटिस क्यों लेते हैं, आप अपनी बात जारी रखिए।

श्री उमाशंकर सिंह : सभापति महोदय, यह राज्य कृषि पर आधारित है । अन्य राज्य उड़िसा भी है, अन्य राज्यों की तुलना में यहां पर सबसे उच्च कोटि का केला होता है, जिसकी फैक्टरी यहां पर लग सकती है, सबसे उच्च कोटि का यहां पर लीची होता है लेकिन यहां पर फुड प्रोसेसिंग का फैक्टरी नहीं चल रहा है । छोटे-छोटे उद्योगों को, गांवों में कुटीर उद्योग का दर्जा दे करके , बैंकों पर दबाव दे करके , चाहे इसमें भारत सरकार से मदद लेना पड़े तो लिया जाय और बैंकों से ऋण मुहैय्या कराया जाय और सरकार उसको उद्योग का दर्जा दे तो उससे कृषि का उपज बढ़ेगा । चूँकि अभी भी इस राज्यकी जो भूमि है, 3468 कि0मी0 लम्बा तटबंध बनाया गया है बाढ़ से सुरक्षा के लिए, जिससे मात्र 29 लाख हेक्टेयर जमीन की सुरक्षा हो रही है। अभी लगभग 40 लाख हेक्टेयर जमीन पर तटबंध बनाने से बाढ़ से सुरक्षा होगी, जिसका रूपया भारत सरकार देती है, उसका भी ये उपयोग नहीं करते हैं । रोज ढिंढोरा पीटते हैं कि बाढ़ से सुरक्षा कर रहे हैं ।

सभापति महोदय, राष्ट्रीय आयोग का कुल जल जमाव 9.41 लाख हेक्टेयर है, जिसमें अब तक जल जमाव से 1 लाख 50 हजार हेक्टेयर ही भूमि मुक्त हो पायी है, जबकि 2 लाख 50 हजार हेक्टेयर भूमि से जल जमाव मुक्त नहीं हो पाया है। सरकार के दृष्टिकोण में और 5.41 लाख हेक्टेयर जल जमाव से मुक्त होने वाला क्षेत्र है । सरकार को इस पर चिन्तन करना चाहिए लेकिन सरकार कोई सकारात्मक कदम नहीं उठा रही है । इसीलिए वह जमीन कृषि के लायक नहीं है । सरकार का कहना है कि इसके लिए करीब 1200 करोड़ रूपया चाहिए । सभापति महोदय,जो कृषि लायक जमीन है, उसमें बिहार में अब सिंचाई सृजन की क्षमता 58.915 लाख हेक्टेयर आंकी गई है । अभी तक सृजित आंकड़ा के मुताबिक 26.17 लाख हेक्टेयर

भूमि में सिंचाई के लिए क्षमता सृजित की गई है । अभी भी 32.750 लाख हेक्टेयर भूमि बिहार में सिंचाई की सुविधा से वंचित है अर्थात सिंचाई क्षमता सृजित की जानी है, जिस दिशा में सरकार का कोई ठोस और सकारात्मक प्रयास दिखाई नहीं देता है ।

सभापति महोदय, बिहार को बाढ़ से बचाने का सवाल है और यह सरकार कहती है कि भारत सरकार नेपाल सरकार से बात करे । यह सरकार समय टाल रही है । नेपाल से कभी भी वार्त्ता होगा, नेपाल उसको टालता रहेगा । पिछले वर्ष सिंचाई विभाग के सचिव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि नेपाल गया था लेकिन परिणाम शून्य निकला । चूँकि नेपाल बराबर इसको टालता रहता है । सरकार इसकी वैकल्पिक व्यवस्था करे, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूँ । बाढ़ से और जल जमाव से इस राज्य को बचाया जाय तभी इस राज्य का कल्याण होगा । निश्चित रूप से स्वभाविक है कि राज्य के बंटने के बाद जितने खनिज-सम्पदा थे, जितने उद्योग थे, वे सब झारखंड में चले गये, आर्थिक नुकसान हुआ है इस राज्य को । वैकल्पिक व्यवस्था यह है कि गंगा के पानी को रोककर बराज बनाईए । जो योजनायें सरकार बनाती है, कोशी डैम योजना है, कमला है, कई योजनायें हैं, उसपर बराज बनाईए, बांध बनाईए और पानी को एकत्रित कीजिए, जिससे सिंचाई उपलब्ध हो । सभापति महोदय, इससे पनबिजली सबसे सस्ता उपलब्ध होगा । बिजली की जो स्थिति है, आज बिजली दे नहीं रहे हैं। 850 मेगावाट बिजली की आवश्यकता इस राज्य को है और 100-200 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है । पनबिजली से बिजली सस्ता मिलेगी और इससे किसानों को लाभ होगा । इसलिए मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि सरकार इस पर चिन्तन करे और सरकार कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे ।

सभापति(श्री अनूप लाल यादव): सरकार इस पर गंभीरता से सोच रही है और इसके अनुरूप सरकार काम करेगी । यह सरकार की मानसिकता है, भारत सरकार नेपाल सरकार से बात करेगी । बाढ़ से सुरक्षा करने के लिए सरकार तत्पर है ।

श्री उमाशंकर सिंह : जब आसन का निदेशन है तो ठीक है । अब मैं पथ निर्माण की बात कर रहा हूँ ।

(क्रमशः)

टर्न-11/19-7-2002/मुस्ताक

श्री उमाशंकर सिंह (क्रमश:) :- सभापति महोदय, पथ निर्माण विभाग की अन्य राज्यों की सड़कों से तुलना करें तो देखेंगे कि - - -

सभापति (श्री अनुप लाल यादव) :- जल संसाधन पर हो गया, फिर पथ पर बोल रहे हैं, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्री उमाशंकर सिंह :- कुछ कुछ सब पर बोलेंगे, मंत्रिमंडल पर बहस हो रही है ।

सभापति (श्री अनुप लाल यादव) :- एक दो सब्जेक्ट ले लीजिए ।

श्री उमाशंकर सिंह :- अन्य राज्य आन्ध्र प्रदेश में पथ निर्माण की सड़कों की लंबाई 8806 कि0 मी0 है, गुजरात में 19761 कि0 मी0 है, कर्नाटक में 11395 कि0 मी0 है, मध्य प्रदेश में 11709 कि0 मी0 है, महाराष्ट्र में 32359 कि0 मी0 है, राजस्थान में 10047 कि0 मी0 है, उत्तर प्रदेश में 9647 कि0 मी0 है, उड़ीसा जैसे छोटे राज्य में 4584 कि0 मी0 है और बिहार में मात्र 4000 कि0 मी0 पी0डब्लू0 डी0 की सड़कें हैं । इसके मायने यह हुआ कि एक इंच भी पथ निर्माण की सड़क में इजाफा नहीं किया है । जब श्री नीतीश कुमार सरफेस ट्रांसपोर्ट मंत्री थे तो उन्होंने हजारों कि0मी0 सड़कों को राष्ट्रीय उच्च पथ में तब्दील किया और आप पी0डब्लू0 डी0 की सड़कोंमें कुछ भी तब्दील नहीं किये हैं । आज गांव की सड़कों की, जिला परिषद् की सड़कों की हालत और आर0 ई0 ओ0 की सड़कों की हालत क्या है, यह चलने लायक नहीं है, बैठे हुए हैं ग्रामीण विकास मंत्री, दरौंदा से महाराजगंज की सड़क पर वे चलें तो उन्हें पता चल जायेगा ।

सभापति (श्री अनुप लाल यादव) :- आप आसन की तरफ देखिये, लाल बत्ती भी जल गयी है ।

श्री उमाशंकर सिंह :- ये पथ निर्माण विभाग की सड़कों की बात मैंने कही और आता हूं मैं 600 करोड़ रु0 पथ निर्माण विभाग को उग्रवाद प्रभावित इलाके के लिए मिला, 600 करोड़ रु0 मिला, 90 प्रतिशत खर्च हुआ और तीस प्रतिशत सड़कें बनी, यह बात समझ में नहीं आती है; सड़क बनी तीस प्रतिशत और खर्च हुआ 90 प्रतिशत,

आज आपने जांच करने के लिए कहा है, तभी मैं खुल जायेगा जो करोड़ों रु० पंचायतों को मिलता है, जमीन पर वह है, एक ब्लॉक की जांच करने की बात है। यह कहते हैं कि यूटिलाईजेशन सर्टीफीकेट दीजिएगा। पथ निर्माण विभाग ने यूटिलाईजेशन सर्टीफीकेट नहीं दिया तो 376 करोड़ रु० बाकी [illegible] रह गया, जब सी०एम०जी० और मंत्री बैठें रांची में तब [illegible] मिला।

श्री विनोद कुमार यादवेंदु :- 6 अरब रु० बिहार को नहीं मिला और आपके केन्द्रीय मंत्री तथा उप प्रधान मंत्री ने इस बात को माना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री लालू प्रसाद यादव ने जब संसद में यह आवाज उठाई, बिहार का हिस्सा सेन्ट्र नहीं दे रहा है।

श्री उमाशंकर सिंह :- यह सारे खर्च इस राज्य की 9 करोड़ जनता की गाढ़ी कमायी, खून पसीना की कमाई को सदन से खर्च करने को इन्हें मिला है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब 1952 में मंत्रिमंडल का आकार बढ़ा तो, 1952 में पहली बार 9 से 14 मंत्री बनाये गये तो स्वर्गीय पंडित रामानंद तिवारी ने कहा कि अब यह राज्य इस बोझ को बर्दास्त नहीं कर सकेगा। आज आप देखें कि पिछली बार 2000-2001 में मंत्रिमंडल पर 54 लाख रु० खर्च हुआ 2001-2002 में 3 करोड़ 7 लाख रु० की बढ़ोतरी हो गयी, जब 9 से 14 मंत्री हुए थे तो स्वर्गीय पंडित रामानन्द तिवारी ने यह कहा था कि यह बोझ राज्य बर्दास्त नहीं कर सकेगा आज उनके पुत्र श्री शिवानंद तिवारी बैठे हैं, राजद सुप्रीमों के सलाहकार कहते हैं कि सभी पार्टी को तोड़कर सबको मंत्री बना दें, 100 से 150 मंत्री बना दें, चाहे राज्य का खजाना खाली हो जाए।

क्रमशः:

टर्न-12/ज्योति/18-7-2002

क्रमशः

श्री उमाशंकर सिंह : जहाँ तक शिक्षा की बात है यह सरकार कर्पूरी जी के नाम पर चल रही है । कर्पूरी जी ने अंग्रेजी हटाओ का नारा दिया था लेकिन दुख की बात है कि यह सरकार तीसरे वेग० वर्ग से अंग्रेजी को अनिवार्य कर रही है ।

(व्यवधान)

हम कर्पूरी जी के साथ 77 में एम०एल०ए० थे । 1977 के बाद से लगातार रहे । आज इस सरकार में शिक्षा नीति के तहत इन्टरमीडियेट की पढ़ाई चार स्तरों पर होती है । कंस्टीच्युएन्ट कॉलेज के अंदर पढ़ाई होती है, एफीलियेटेड डिग्री कॉलेज में पढ़ाई होती है, अपग्रेडेड हाई स्कूल प्लस टू में पढ़ाई होती है और 465 इन्टरमीडियेट वित्त रहित कॉलेज में इन्टरमीडियेट की पढ़ाई होती है । वित्त रहित कॉलेजों के लिए जगदानंद सिंह की अध्यक्षता में कमिटी वर्षों से बनी हुई है आज वित्त रहित के लाखों शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारी के सामने भुखमरी की समस्या है । इन चार स्तरों में से तीन स्तरों में पैसा मिल रहा है -कंस्टीच्युएन्ट कॉलेज में मिल रहा है, जो अपग्रेडेड हाई स्कूल है उनके लोगों को पैसा मिलता है, जो एफिलियेटेड डिग्री कॉलेज है उनको यू०जी०सी० से ग्रान्ट मिलता है ।

सभापति (श्री अनूप लाल यादव): माननीय सदस्य उमा शंकर सिंह जी आप पुराने माननीय सदस्य है, बहुत लोग बोलने वाले हैं अब समाप्त करिये ।

श्री उमाशंकर सिंह : वित्त रहित शिक्षा नीति के चलते सारी शिक्षा चौपट है । प्राथमिक विद्यालयों के भवन नही है, शिक्षक नहीं हैं । जहाँ शिक्षक हैं वहाँ भवन नहीं हैं और जहाँ भवन हैं वहाँ शिक्षक नहीं है । यह स्थिति पूरे राज्य की है । हर स्तर पर सरकार का फेल्योर है ।

सभापति (श्री अनूप लाल यादव): मा० सदस्य आप आसन ग्रहण कर लें, आसन की बात को मान लीजिये आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री उमाशंकर सिंह : इनकी शिक्षा नीति गलत है । शिक्षा मंत्री से हटा दिए गए थे, इनसे शिक्षा विभाग ले लिया गया । हम कहना चाहते हैं कि सरकार इन सब बातों की छानबीन करे । यह तो शिक्षा की बात हुई । स्वास्थ्य मंत्री बैठे हुए हैं, स्वास्थ्य को क्या हालत है ? स्वास्थ्य मंत्री का अपना ईलाज यहाँ नहीं हो रहा है । इन्होंने 14 सौ डौक्टरों का एक बार में तबादला किया है । अब मैं अपना कंक्लुड कर रहा हूँ ।

श्री नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा: यहाँ उद्योग नहीं हैं और उद्योग मंत्री हैं और स्वास्थ्य नहीं हैं और स्वास्थ्य मंत्री हैं ।

श्री शकुनी चौधरी, मंत्री: सभापति महोदय, नवीन जी के चेहरे से आप समझ सकते हैं कि बिहार का स्वास्थ्य कैसा है और उमाशंकर बाबू की मूछ देखिये । इन लोगों को देखकर महसूस कर सकते हैं कि यहाँ का स्वास्थ्य कैसा है ।

श्री रवीन्द्र चरण यादव: नवीन जी क्या बात करते हैं वे तो 5 आदमी मिलकर मूली उखाड़ने का काम करते हैं, अकेले क्या करेंगे ।

श्री नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा : जयप्रकाश बाबू को भूल गए जिन्होंने पूरे भारत से कांग्रेस और इन्दिरा गांधी को उखाड़ दिया था ।

श्री उमाशंकर सिंह : इस राज्य के एक राज्यमंत्री की चर्चा करता हूँ । राज्य मंत्री गृह सचिव के कक्ष में सचिवालय में जाकर 40-45 मिनट तक बैठे रहे, समता पार्टी के कई विधायक वहाँ गए थे उस समय उनसे मुलाकात हुई थी । यह शर्म की बात है कि मंत्री लोग जाकर सचिवालय में किसी पदाधिकारी के चैम्बर में जाकर बैठे और प्रतीक्षा करें ऐसे सरकार की क्या बात कही जाय ।

श्री सुशील कुमार मोदी, ने०वि०दल : सभापति महोदय, मुझको जानकारी मिली है बिहार सरकार के एक मंत्री हत्या के मामले में जिनको आज ही 12 बजे आजीवन कारावास की सजा मिली है और वे जेल में चले गए हैं । इसके बारे में सदन को सूचना मिलनी चाहिए । ऐसे ऐसे मंत्री रखेंगे तो मंत्रिमंडल का काम कैसे चलेगा । रामाश्रय सहनी इनके पशुपालन मंत्री हैं, पशुपालन विभाग का दुर्भाग्य है कि जो कोई मंत्री बनता है वह जेल चला जाता है । 20 साल के कारावास की सजा उनको हुई है । उनके बारे में सदन में अविलंब घोषणा होनी चाहिए ।

श्री राम चन्द्र पूर्वे, मंत्री: महोदय, उनका इस्तीफा हो०००००चै० आ चुका है, उस इस्तीफे को महामहिम राज्यपाल के यहाँ भेजने की कार्यवाई हो रही है ।

टर्न-13/ विजय 18.7.02

श्री रामदेव राम: सभापति महोदय, मैं मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार, संसदीय कार्य विभाग के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, बिहार में जो मंत्रिमंडल है इस पर एक दोहे के माध्यम से ... करना चाहता हूं - कबीर दास का एक दोहा है :

" बड़ा हुए तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर,
पथिक को छाया न मिले फल लगे अरगूर "

सभापति महोदय, इस मंत्रिमंडल के लिए उपरोक्त दोहा काफी प्रासंगिक हो गयी है। बिहार की जनता के उपर यह मंत्रिमंडल बोझ बन गया है। महोदय, छोटे ... मंत्रिमंडल से एक ...

अच्छा बिहार, एक नया बिहार बनाया जा सकता है। लेकिन इस सरकार की कमजोरियां उजागर हो जाती हैं। इतने बड़े मंत्रिमंडल से यह सरकार विभिन्न मार्चों पर विफल रही है और अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए, किसी तरह से सरकार को बचाने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार लगातार होता जा रहा है। जम्बो ... मंत्रिमंडल बनाया गया है। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि इस बिहार में सबसे बड़ा भूमि सुधार कानून बना। लेकिन आज तक भूमिसुधार का काम बिहार में लागू नहीं हो सका। सामाजिक न्याय की सरकार दलितों, ... पिछड़ों, अति पिछड़ों की कहलाने वाली सरकार विगत 12 वर्षों से इस बिहार में सत्तासीन है लेकिन बिहार में भूमिसुधार कार्यक्रम ... लागू नहीं कर ... सकी है। महोदय, इस मंत्रिमंडल की विफलता का एक नमूना है। इंदिरा आवास के संबंध में माननीय श्री जय प्रकाश ना0 यादव जी कल कह रहे थे कि 10 लाख इंदिरा आवास बना है। मैं बताना चाहता हूं कि सरकार का उसमें कितना हिस्सा है। 20 हजार की ... राशि में 3 से 5 हजार तक की राशि बिचौलिए ले लेते हैं घूस ले लेते हैं यह मंत्रिमंडल इसको रोक नहीं पाया है। बिचौलिये और पदाधिकारी ने पैसा ले लिया। इंदिरा आवास योजना में आपकी कोई भूमिका नहीं है। आप हिसाब किताब करके देख लीजिये।

दूसरी बात कहना चाहता हूं भूमि वितरण का काम जो हुआ दावे के साथ कहता हूं कि वह महज कागज पर है मंत्री के आजगन में है गरीबों को गैर मजरूआ और बासगीत का पर्चा नहीं मिला है, कब्जा नहीं मिला है।

क्रमश:

टर्न-14/राजेश/18.7.2002

श्री सत्यदेव राम(क्रमशः):- और आपने, उनको ऑफिस में बैठे-बैठे, पर्चा काटकर दे दिया है और गांव-गांव में लड़ाई झगड़ा को पैदा करा दिया है, जबकि सरकारी जमीन आपको नहीं है, लेकिन आपने- बैठे-बैठे पर्चा दे दिया, इसलिए हम आपके माध्यम से, इस मंत्रिमंडल से अपील करेंगे कि आप इसको समाप्त कीजिये, नहीं तो अगर आपमें दम है, तो आप गरीबों के बच्चों को कब्जा दिलाने के लिए अपने ऑफिसर को आदेश दीजिये । हलांकि मैं जानता हूँ कि इसमंत्रिमंडल का आदेश नहीं चलता है, इनके आदेश को इनके ही ऑफिसर नहीं मानते हैं और आपमें दम भी नहीं है कि आप आदेश दीजिये । सभापति महोदय, भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद जी ने, इसी सदन में घोषणा किये थे कि बिहार में गैरमजरूआ फालतू सरकारी जितनी जमीन है, उसपर अगर हमारे गरीब लोग कब्जा करेंगे तो हमारी पुलिस उनपर गोली नहीं चलायेगी । लेकिन महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि जैसे ही गरीब लोग इस काम के लिए बढ़े, उन गरीबों पर गोलियों से बौछार हो गयी और इसमें अनेकों लोग मारे गये । यह हालत है । अभी एक माननीय सदस्य, पंचायत चुनाव की चर्चा बड़े ही जोर-शोर से कर रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके इस मंत्रिमंडल में अगर दम है तो आपने गरीबों को, दलितों को आरक्षण क्यों नहीं दिया और इसका नतीजा यह हुआ कि आज पूरे बिहार में लगभग ढ़ाई हजार मुखिया बनने से ये लोग वंचित हो गये । इसलिए मैं आपलोगों से पूछना चाहता हूँ कि आखिर मंत्रिमंडल को क्या भूमिका है या आपमें क्या शक्ति है, आपका मंत्रिमंडल तो सिर्फ इस बिहार को लूटने का काम कर रहा है, बिहार के विकास के बारे में कोई काम नहीं कर रहा है और न उस ओर यह मंत्रिमंडल सोच ही रहा है, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ ।

इसके अतिरिक्त सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो विधान-सभा क्षेत्र है, वह सटे हुए उत्तरप्रदेश से है और वहाँ पर एक प्रतापपुर चीनी मिल लगा हुआ है, उस चीनी मिल में यू0पी0और बिहार का गन्ना आता है और महोदय, जब यू0पी0और बिहार के यानि की दोनों राज्यों के किसान गन्ना लेकर आते हैं तो यू0पी0के गन्ना किसानों को 100 रूपया प्रति क्विंटल मिलता है और बिहार के गन्ना किसानों को उसी मिल में, 86 रूपया प्रति क्विंटल के रेट से पेमेन्ट किया जाता है । क्या इसके लिए आपके मंत्रिमंडल को ताकत है कि वह इसको देखे, नहीं ताकत है, आपलोगों में यह हिम्मत नहीं है और आज इसी का नतीजा है कि बिहार के किसानों का गन्ना 14 रूपये प्रति क्विंटल के रेट से, कम दिया जाता है और इसतरह से महोदय, साढ़े तीन करोड़

रुपया बिहार के किसानों का नुकसान हुआ है, उनको घाटा उठाना पड़ा है। इसके अतिरिक्त महोदय, आज तक यह सरकार बिहार के गन्ना किसानों के लिए तो मूल्य तक नहीं तय कर पायी है, पता नहीं यह सरकार किस निद्रा में सोयी हुई है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ, यहाँ पक्ष और विपक्ष एवं अन्य सभी दलों के लोग, बैठे हुए हैं और हमलोग एक दूसरे को आलोचना इसलिए करते हैं कि हम भी सत्ता में आवें, लेकिन महोदय, आपको याद होगा कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद जी ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी को, कांग्रेस को सरकार को, उसके खनदानीवाद को, उसको निरंकुशता पर ही, हमारे लालू प्रसाद जी ने यहाँ पर सरकार बनाया था, लेकिन आज लालू जी कहाँ चले गये, आप सरकार कैसा चला रहे हैं? सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज यह सारी गरिमा ही समाप्त हो गयी है।

क्रमशः:

•श्री सत्यदेव राम: क्रमश: : आज हमलोग एक दूसरे की आलोचना. बिहार की जनता के लिए नहीं करते हैं, बिहार की हित के लिए नहीं करते हैं, बिहार के विकास के लिए नहीं करते हैं, बल्कि अपनी हित के लिए करते हैं । इसकी गंभीरता पर मंत्रिमंडल को विचार करना चाहिए ।

एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान के किसी भी राज्य में कोई मुख्य मंत्री है, तो वहां कोई पुरूष मुख्य मंत्री है या महिला मुख्यमंत्री है लेकिन बिहार में नर-नारी मुख्यमंत्री हैं, पति-पत्नी मुख्यमंत्री हैं । यहां नर-नारी की सरकार चलती है । यहां नर-नारी की ज्वायंट सरकार है और यह सरकार कभी भी बिहार के विकास के लिए, दलितों की सुरक्षा के लिए, गरीबों की रक्षा के लिए काम नहीं कर सकी । यह सरकार मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं दे सकी और यह जम्बो-जेट मंत्रिमंडल सिर्फ कहने के लिए है । इस सरकार के पास काम करने के लिए इच्छा शक्ति नहीं है, आत्म-शक्ति नहीं है । इस सरकार को आत्म-शक्ति, इच्छा शक्ति बनानी चाहिए नहीं तो यह भी सरकार इस जगह पर लम्बे समय तक रहकर चली जायेगी और आपका 12 वर्षों का कारनामा बिहार की जनता के सामने रहेगा । इसमें आप सुधार कीजिये । यही मेरा अनुरोध है ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ ।

श्री रामदेव यादव: सभापति महोदय, सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है, उसके पक्ष में मैं बोलने के खड़ा हुआ हूँ ।

लगातार कल और आज से विभिन्न माननीय सदस्यों ने यहां विस्तार पूर्वक चर्चा की है । मैं कहना चाहूंगा कि गणेश बाबू ने कई सवाल उठाये, कई माननीय सदस्यों ने कई सवाल उठाये कि बदले की भावना से गृह विशेष विभाग, पुलिस विभाग के लोगों ने माननीय सदस्य ललित यादव पर चोरी का केस लगाया । वे यहां सदन में बैठे हुए हैं । वे आज भी इसी सदन के सदस्य हैं और मंत्री थे । यहां सदन में माननीय नेता, विरोधी दल, मोदी जी चिल्ला-चिल्लाकर कहा करते थे कि ललित यादव ने एक बैठा को मारा-पीटा, उसका नाखून उखाड़ा जबकि यह एक नाटक था । कोर्ट ने भी उनको बरी कर दिया है । माननीय नेता, विरोधी दल टी0 भी0 पर हल्ला करके माननीय सदस्य को फंसाने का काम किया । उस समय आप बदले की भावना से काम कर रहे थे चूंकि वे सत्ता पक्ष के लोग थे । लेकिन आये दिन कई ऐसे मामले हो रहे हैं जिसका

टर्न 15 : 18.7.02,
सच्चिदा ।

खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपलोगों को । आप नहीं बचियेगा इससे । इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि माननीया श्रीमती राबड़ी देवी की जो सरकार लगातार 12 वर्षों से है, सब... उनलोगों को बोलने की आजादी दी है, जो हजारों वर्षों से नहीं बोलते थे । इस बात को आप इनकार नहीं सकते । जो लोग घर में बैठे रहते थे, जिनको बंधुआ मजदूर बनाकर रखते थे, आज वे लोग सड़क पर आये हैं और यह काम माननीया मुख्य मंत्री श्रीमती राबड़ी देवी ने की है । उनलोगों को मुख्य धारा में लाने का काम किया है । हमारे दलित समाज के जो लोग हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनको मुख्य धारा में लाने का काम राष्ट्रीय जनता दल ने किया है । यह एक सराहनीय बात है ।

(क्रमशः)

श्री रामदेव यादव - क्र मशः :- वह एक सराहनीय काम है। यह बात मैं आपको बताना चाहता हूं। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज से 12 साल पहले, 20 साल पहले कोई गरीब का बेटा, कोई कुम्हार का बेटा डर से थाने नहीं जाता था। गांव का जमींदार जो होते थे, उनकी चलती गांवों में होती थी। आज स्थिति बदल गई है। हमारी सरकार में, सामाजिक न्याय की सरकार में गरीब का बेटा भी बिहार की इस धरती पर विधायक बना है। आपने देखा होगा। दरभंगा के डोम जाति के लोग भी इस विधान-सभा में निकल किये हैं। आज लालू यादव की धारा है और इस धारा में बड़े पैमाने पर पिछड़े और लोग आ रहे हैं। नहीं तो इनलोगों को भी यहां जगह नहीं मिल पाती ।

महोदय, मैं पुलिस विभाग के संबंध में कुछ बातें कहना चाहता हूं। झारखंड अलग हुआ। शेष बिहार बचा। लगातार झारखंड के उग्रवाद जो वहां पनप रहे हैं, जिसका विस्तार बांका और जमुई जिला में हो रहा था उसको समाप्त करने की दिशा में पुलिस विभाग ने काम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, साथ ही एक सूचना देना चाहता हूं कि कल चीफ कमान्डर सुरेन्द्र पंडित ने पुलिस के राईफल और कारबाईन के साथ सरेंडर किया है। इसलिए मैं बधाई देते हुये कहना चाहता हूं कि यह काम माननीय लालू और राबड़ी देवी के शासनकाल में हुआ है।

महोदय, जो गरीब लोग गाय-भैंस चरानेवाले हैं, सुखी लकड़ियां चुननेवाले है, उनको नक्सलाईट वाले शोषण करते थे। उन पर टैक्स लगाते थे। आज मैं

बताना चाहता हूं कि बड़े-बड़े पुल बन रहे है। उसको उग्रवादियों ने उड़ाने का प्रयास किया था। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के मुख्यमंत्री के गृह जिला गिरिडीह में पुलिस द्वारा बढ़ा दी यहां के उग्रवाद बांका और जमुई जिला की ओर आने का काम किया है। तो यहां का पुलिस विभाग, डी०जी०पी० यहां बैठे हुये हैं, श्री नीतान्जी/साहब ने वहां स्पेशल टास्क फोर्स को भेजा, था और वहां लगातार छापामारी की गई और पुलिस के जो राईफल और कारबाईन लूटे गये थे, उसको इस पुलिस ने बरामद करने का काम किया है।

महोदय, भागलपुर में गंगा नदी पर पुल बना। चुआ नदी पर बांका जिला में 37 स्पैन का 5 करोड़ रूपये की लागत से पुल बना, यह सब माननीया श्रीमती राबड़ी देवी की सरकार की उपलब्धि है। इसलिए मैं पथ निर्माण विभाग के मंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूं।

§ व्यवधान §

श्री गणेश पासवान - सभापति महोदय, मेरे खिलाफ जो आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग हुआ है उसको कार्यवाही से निकलवा दिया जाये।

श्री उमाशंकर सिंह - सभापति महोदय, इस तरह की बात प्रोसिडिंग्स में नहीं जाना चाहिए।

§ इस अवसर पर समता पार्टी के कुछ माननीय सदस्यगण वेल में आ गये §

सभापति §श्री अनूप लाल यादव§- इस तरह की बात को कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

डॉ0 रामचन्द्र पूर्वे (मंत्री) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य द्वारा यदि किसी असंसदीय शब्द का इस्तेमाल हुआ हो तो उसे कृपया प्रोसिडिंग्स से निकलवा दिया जाय ।

सभापति (श्री अनूप लाल यादव) : इसके लिये हमने निदेश दे दिया है ।

(इस अवसर पर समता पार्टी के माननीय सदस्यगण सदन के "वेल" से चले गये।)

श्री रामदेव यादव : सभापति महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी इस सरकार को काफी उपलब्धि मिली है । इन्दिरा आवास की लोग चर्चा करते हैं, आज से 20 साल पहले इन्दिरा आवास क्यों नहीं बनता था, आज गाँव के मुसहर, गाँव के दलित, गाँव के पिछड़े जो बेघर लोग हैं, उनका मकान बना है । आज पक्के के मकान में दलित का बेटा सो रहा है इसलिए इनलोगों को दिक्कत और तकलीफ हो रही है ।

सभापति महोदय, वर्तमान सरकार में यह इच्छाशक्ति है कि गरीब-दलित लोगों को जिनको हजारों वर्षों से दबाया गया, कुचला गया है, उन्हें मुख्यधारा में आगे बढ़ाने का काम वर्तमान सरकार कर रही है और करती रहेगी ।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि बिहार सरकार काम नहीं कर रही है, हर क्षेत्र में मैं कहना चाहता हूँ और उदाहरण देकर कहना चाहता हूँ, आज पक्ष और विपक्ष में जो भी माननीय सदस्य बैठे हैं, यदि एक करोड़ रूपया राबड़ी देवी जी की सरकार आपको नहीं देती तो आप जनता के बीच मुँह दिखाने नहीं जा सकते थे । इसके लिए मैं माननीय राबड़ी देवी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि आज माननीय सदस्यों को घूमने-फिरने और विकास करने का मौका मिला है और यह राबड़ी देवी की सरकार की देन है ।

सभापति (श्री अनूप लाल यादव) : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें ।

टर्न-17/मधुप/18.7.2002

श्री रामदेव महतो : महोदय, आपको याद होगा, पूर्व की सरकार द्वारा मात्र तीन लाख रुपया प्रत्येक विधायक को दिया जाता था लेकिन आज विपक्ष के लोगों को भी माननीया राबड़ी देवी की सरकार को बधाई देना चाहिये कि प्रत्येक विधायकों को एक करोड़ रुपया देकर एक बहुत बड़ा काम किया है। महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि हमने महुआ नदी पर पुल बनवाया, लंबई नदी पर पुल बनवाया है। तमाम जगहों में बड़े-बड़े काम हुये हैं, पी०सी०सी० सड़क बनाने का काम किया गया है। अगर आप अपना दिमाग और बुद्धि लगायेंगे और उस पैसे का सदुपयोग करना चाहेंगे तो एक करोड़ रुपया एक साल में खर्च करने के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा।

इसलिए भाईयों, इस बात को आपलोगों को स्वीकार करना चाहिये कि इस सरकार ने जो काम किया है, वह इस राज्य के तमाम दलित और गरीब लोगों के लिये काम किया है। इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री विजय कुमार मिश्र : सभापति महोदय, मंत्रिपरिषद् के बारे में जो कटौती-प्रस्ताव रखा गया है उसके पक्ष में मैं बोल रहा हूँ। मंत्रिपरिषद् के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है क्योंकि हमारे साथी सत्ता पक्ष के ललित बाबू ने कहा कि यह मंत्रिमंडल पिछले 10-12 सालों से लेकर आगे और 10-12 सालों तक बिहार की जनता के सीने पर दाल दलते रहेंगे। आप दाल दलते रहिये, यह आपका काम है। लेकिन आज हो क्या रहा है? इस मंत्रिमंडल के बारे में मेरा ख्याल है कि यदि न्यायपालिका नहीं रहती तो कोई भी विकास का काम नहीं होता। पथ निर्माण विभाग से यदि शुरू किया जाय तो अगर पथ निर्माण कराने के लिये माननीय विपक्ष के नेता, मोदी जी वगैरह हाईकोर्ट नहीं गये होते, सी०बी०आई० जाँच नहीं हुई होती तो पथ निर्माण का सारा काम बन्द हो गया होता। जिस तरफ देखिये, वही हाल है। एक साथी ने कहा कि हमलोग हॉस्पीटल और स्वास्थ्य के लिये बहुत काम कर रहे हैं लेकिन मैं बताना

चाहता हूँ कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री, शकुनी चौधरी जी ने जो भी डॉक्टरों की बदली की है, न्यायपालिका के कारण किया है । मंत्रिमंडल के द्वारा पिछले 10-12 सालों में कोई काम नहीं किया गया है ।

(क्रमशः)-

श्री विजय कुमार मिश्रा : (क्रमशः) आपका जो भी काम हो रहा है, वह हाईकोर्ट के माध्यम से कराया जा रहा है, यह दुर्भाग्य की बात है । हम सभी लोग इस बात से दुःखी है कि कार्यपालिका पर न्यायपालिका हावी हो रहा है सुप्रीम कोर्ट हो या हाईकोर्ट हो । इसलिए यह मंत्रिमंडल जो भी विकास का काम कर रही है, न्यायपालिका के बल पर कर रही है, उसके निर्देश पर कर रही है । हमारे साथियों ने कहा कि बिहार में 22 साल के बाद पंचायत चुनाव हुए हैं, मुखिया का चुनाव हुआ है । सभापतिजी, आप भी 40 साल से सदस्य रहे हैं, अगर न्यायपालिका नहीं होती, एन0डी0ए0 की सरकार केन्द्र में नहीं होती तो यहां पर पंचायत के चुनाव नहीं होते । स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी 1977 ईसवी में चुनाव कराये और मेरे ख्याल से जो भी राज्य चल रहा है, उसमें स्व0 कर्पूरी ठाकुर का श्रेय रहा है । 1978 के बाद पंचायत के चुनाव क्यों नहीं हो पाये । 12 साल से यह सरकार है और कल ही राज्य सभा में कहा जा रहा था कि 600 करोड रू0 केन्द्र सरकार ने नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, चूँकि पंचायत चुनाव नहीं हुआ। न्यायपालिका के कारण ही आज बिहार में पंचायत के चुनाव हुए हैं, इसके लिए चाहे कितना भी सरकारी पक्ष अपना पीठ थपथपा ले, इसमें किसी का कोई भी योगदान नहीं है । आज मंत्रिमंडल पर बहस चल रहा है, एक मंत्री जी को जेल जाना पड़ा, यह दुर्भाग्य की बात है । मंत्रिमंडल कोई भी हो, प्रजातंत्र में हम और आप सभी एक साथ रहते हैं । हो सकता है मंत्रिमंडल के सदस्य आज हैं, कल वे नहीं रहेंगे लेकिन इस तरह की घटना मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है । मंत्रिमंडल का जो विषय है, लोग कहते हैं कि काम कर रहे हैं । इसी बिहार में आपको याद होगा सभापति जी, महेश्वर मिश्रा जी की अध्यक्षता में एक कमिटी बनी थी, उसमें तय हुआ था कि प्रखंड, सबडिविजन किस तरह से बनाया जाय ?

लेकिन उस कमिटी के रिपोर्ट को देखते हुए राजनीतिक कारण से लोगों को खुश करने के लिए 2 प्रखंड को मिलाकर एक सबडिविजन बना दिया गया । यह ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है, चूंकि एन०डी०ए० की सरकार/भी/ इच्छा रही है, इस सरकार की भी इच्छा रही है कि छोटा प्रशासन रहने से काम ठीक ढंग से होता है लेकिन इसमें भेदभाव होता है । सभापति महोदय, दरभंगा जिला के बारे में कह रहा हूं कि 20-25 साल पहले से यह मांग चल रही थी कि . . . अहिल्यापुर स्थान में एक प्रखंड बनाया जाय मधुबनी एवं दरभंगा के कुछ इलाकों को जोड़कर किसानों के हित में और वहां के लोगों के हित में लेकिन इन सब चीजों को छोड़ते हुए जहां इच्छा हुआ, जहां राजनीतिक प्रेशर हुआ, वहां पर प्रखंड बनाया गया । इसलिए यह कहना कि मंत्रिमंडल द्वारा जो काम हुआ है, वह ठीक ही हुआ है, इस तरह की कोई बात नहीं है । सभापतिजी, जहां से आप आते हैं, मेरा भी घर वहीं पर है । आपको मालूम है कि हमारा घर आपके ही सबडिविजन त्रिवेणीगंज में है । वहां से त्रिवेणीगंज जाने में 40 कि०मी० की दूरी है और राजनीतिक भेद-भाव के कारण वहां से 6 कि०मी० पर विरपुर है, उसको अलग कर दिया गया । इसलिए मैं सत्ता पक्ष से आग्रह करेंगे कि कोई भी विकास के काम में आपका कोई भेद-भाव नहीं होना चाहिए । आज हमारे साथी ने बहुत जोरों से कहा कि यदि आज माननीय मुख्य मंत्री एक करोड़ नहीं दी होती तो विकास का काम यहां पर नहीं हुआ होता, जबकि पहले 3 लाख रू० मिलता था । यह मुझको मालूम है कि पहले 3 लाख मिलता था । लेकिन जो विपक्ष में लोग बैठे हैं, वे लोग मंत्रिमंडल में नहीं हैं, जिस समय 3 लाख और 5 लाख मिलता था । उस समय के मंत्रिमंडल के सदस्य आज भी इस मंत्रिमंडल में भी सदस्य हैं । इसलिए यह कहना कि 3 लाख रू० से एक करोड़ रूपया कर दिया, यह हमारी उपलब्धि है , यह आपकी उपलब्धि नहीं

है । यह तो केन्द्र सरकार की उपलब्धि है, अगर केन्द्र सरकार ने सांसदों को एक करोड़ से दो करोड़ नहीं किया होता तो आज आप एक करोड़ नहीं दिये होते । यह केन्द्र सरकार का पैसा नहीं है लेकिन इंदिरा आवास का पैसा केन्द्र सरकार का है । लोगों ने कहा कि इंदिरा आवास के पैसे का क्या हुआ ? आपको याद हो या न हो, यही सरकार वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब देखा गया कि बिहार में ही नहीं, सभी राज्यों में इंदिरा आवास में भेद-भाव किया गया । कहीं किसी को कम और कहीं किसी को ज्यादा । इसीलिए केन्द्र सरकार ने दिल्ली से ही चार्ट बनाकर सभी ... ब्लौक में कितना-कितना इंदिरा आवास देना चाहिए और इसका मोनेटरिंग केन्द्र सरकार कर रही है ।....

(क्रमशः)

श्री विजय कुमार मिश्रा(क्रमशः):- इसलिए यह कह देना कि इन्दिरा आवास आपकी उपलब्धि है, यह बात ठीक है कि इन्दिरा आवास पहले भी चल रहा था लेकिन आपको इन्दिरा आवास का पैसा बढ़ाने, इन्दिरा आवास तीन भागमें बांटने केन्द्रीय सरकार की उपलब्धि है, आपके बाजपेयी जी की सरकार ने यह मौका दिया, केवल बिहार को ही नहीं दिया पूरे देश को दिया। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि बिहार के लिए कोई विशेष नहीं हुई, विकास के मामले में ठीक काम हुआ या नहीं हुआ, तमाम लोग अपनी छाती पर हाथ रखकर देखियेगा तो पता चल जायेगा कि विकास का काम हुआ या नहीं हुआ ? पिछले पांच वर्षों में केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये विकास कार्य और आपके द्वारा किये गये विकास कार्य कहां रह जाते हैं। एन0 एच0 हो, रेलवे लाईन बिछाने की बात हो या बाढ़ में एन0टी0पी0सी0 का जो बन रहा हो, यह केन्द्रीय सरकार की देन है, हम इस बात को मानते हैं कि जमीन दिलाने में सरकार ने जल्दी काम किया। सभापति महोदय, यह बात ठीक है कि विकास का काम केन्द्रीय और राज्य सरकार दोनों मिलकर ही कर सकती है। पटना में जरा आप घूमकर देखिये यहां के छोटे छोटे व्यापारियों की क्या हालत है, सभी पटना छोड़ कर रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारे बहुत से बचपन के दोस्त हैं जो अपने बेटा बेटी को आजसे दस दिन पहले पटना से बाहर भेज दिया।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव:- गुजरात छोड़कर लोग जा रहे हैं।

श्री विजय कुमार मिश्रा:- गुजरात इसलिए छोड़ दिया, गुजरात में चुनाव होने वाला है। मैं कांग्रेस पार्टी में रह चुका हूं, चुनाव का यदि एक साल नहीं होता तो गुजरात में जो हुआ वह नहीं होता। गुजरात में जो हुआ है, उसका कारण एक साल में चुनाव होना है, अगर चुनाव नहीं होता तो यह घटना नहीं घटती, राजनीतिक पार्टी चुनाव का लाभ लेने के लिए जब कोई मुद्दा नहीं मिला तो यह काम कराया, इसमें हंसने की बात नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। गुजरात की बात को लेकर हम और

आप उसे कहें इससे काम नहीं चलेगा ,आपको गुजरात नहीं अपना बिहार देखना पड़ेगा । बिहार में यह बात ठीक है कि हिन्दू -मुस्लिम कांड नहीं हो रहा है डर है इसलिए नहीं हो रहा है लेकिन दूसरा काम हो रहा है ,वह हिन्दू -मुस्लिम से अधिक हो रहा है । यहां के छोटे छोटे व्यापारी बिहार से जा रहे हैं ,इनको रोकने का काम करें तभी कुछ न कुछ आप कर सकते हैं । ठीक ही कहा बाढ़ के बारे में उमाशंकर बाबू ने कि कहते हैं कि नेपाल से बात करना होगा ,यह बातें पिछले 50 सालों से हो रही है ,हम नेपाल के भरोसे बिहार को नहीं छोड़ सकते हैं । बहुत सी योजनायें हैं जिन्हें बनाकर उत्तर बिहार में बाढ़ से रोक थाम की जा सकती है । हमारी बातें पुलिस पदाधिकारी से होती है तो वे लोग परेशान हैं कि हम क्या करें ,सभी लोगों को कुछ करने के पहले फोन आ जाता है । इसलिए मुख्य मंत्री से आग्रह करूंगा कि बिहार में एक स्वस्थ्य वातावरण बनाइये ,12 वर्षों का काम कम नहीं होता है और इस राज्य का जो सिस्टम बना है ,प्रजातंत्र में आपके पास विधायक है , कुछ कीजिए लेकिन ऐसा नहीं कीजिए कि राज्य चलाने के लिए आपकी पार्टी दूसरी पाटी को तोड़ कर राज्य चलाना अच्छी बात नहीं है । आपका राज्य चलेगा ,बिहार के विकास का काम करें सभी लोगों को साथ करें । यह मंत्रिमंडल आपका है,प्रशासन आपका है ,आपके पदाधिकारी हैं हम सब विधायकों को मालूम है कि राज्य आपका चलेगा । जब ब्लौक में बी0डी0ओ0 और सी0 ओ0 नहीं थे तो विधानमंडल में बात उठी

.विधान-मंडल के आरक्षा के दबाव में आपने कार्मिक विभागसे पदाधिकारी भेजा तो आप न्यायपालिका के माध्यम से शासन चलाना चाहते हैं तो इतने बड़े मंत्रिमंडल की क्या आवश्यकता है । लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी बड़ा मंत्रिमंडल है लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा विधायक जितने हैं यहां हैं ,मंत्रिमंडल उससे बड़ा है और दिल्ली में

दिल्ली मंत्रिमंडल एम0 पी0 से कम हैं ,इतना जरूर है कि यहां 70 प्रतिशत विधायक मंत्रिमंडल में हैं ।

माननीय सदस्यगण :- बहुत से लोग लाईन में खड़े हैं ।

श्री विजय कुमार मिश्रा:- यहां भी बहुत से लोग लाईन में लगने की कोशिश कर रहें ।

क्रमश:

टर्न-20/ज्योति/18-7-2002 क्रमशः

•श्री विजय कुमार मिश्र : दिल्ली में बहुत बढ़िया सरकार चल रही है लेकिन जो यहाँ आपकी सरकार चल रही है उसकी बात सोचिये । कितने मंत्रियों को और बढ़ायेंगे । मंत्रियों की संख्या बढ़ाने से विकास नहीं होता है । इसी बिहार में 324 सदस्य हुआ करते थे और छोटे मंत्रिमंडल से विकास का काम होता था और आज 243 सदस्य हैं और जितने विधायक हैं उससे अधिक मंत्रिमंडल के सदस्य की संख्या है । बदसौभाग्य की बात है इस सदन में दो ऐसे माननीय सदस्य हैं एक श्री देवनारायण बाबू और दूसरे सभापति जी आप जिनका हमारे परिवार से व्यक्तिगत संबंध रहा हैं और दो जेनरेशन से हमारे साथ हैं और बिहार को ये लोग देख चुके हैं

ह

इनलोगों के मन को कचोट होता होता, बोले या न बोलें बिहार का इतना बड़ा मंत्रिमंडल बन जाय और उत्तर बिहार के इन दो प्रमुख नेता को उस मंत्रिमंडल में नहीं रहना पड़े -यह क्या है ?इनलोगों से पूछिये । आज कोई भी विकास का काम ठीक ढंग से नहीं चल रहा है । अब मैं विधायक फंड के बारे में कहना चाहता हूँ कि यह बात ठीक है कि यदि विधायकफंड नहीं होता तो हम लोगों के क्षेत्र का विकास नहीं होता । हमारे क्षेत्र का भी विकास नहीं होता और आपके क्षेत्र का भी विकास नहीं होता । अब देखना यह होगा कि पंचायती राज बनने के बाद जिला पर्षद और पंचायत पर्षद के लोग कौन कौम काम करते हैं । अभी इसमें पैसे की कमी नहीं हैं अगर आपस में कोओर्डिनेशन हो जाय विधायक के साथ, जिला पर्षद के साथ और पंचायत पर्षद के साथ तो कोई भी विधान सभा क्षेत्र की तरक्की को नहीं रोक सकता है, यातायात के मामले में भी हम काम को अच्छा कर सकते हैं । कल की बात है हमारे एक साथी ने कहा कि पूर्वे जी मंत्री बैठे हुए हैं, पूर्वे जी के बारे में एक चीज याद आ जाती है कि ये शिक्षा मंत्री हैं लेकिन पूर्वे जी से शिक्षा विभाग ले लिया गया है और यह रमण जी के पास चला गया है आज शिक्षा विभाग में क्या हो रहा है । आज हाई स्कूल भवन बनाने के लिए फंड नहीं है, मीडिल स्कूल और प्राथमिक स्कूल के लिए फंड है और फंड रहते हुएभी काम नहीं हो रहा है । गोपालगंज जेल के बारे में प्रश्न आया था उसके बारे में बतलाया गया कि केन्द्र सरकार

से पैसा आया हुआ है जेल बनाने के लिए लेकिन उस पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा है, पैसे का बंदरबाट कर रहे हैं। जो भी केन्द्र से पैसा आता है उस पैसे के लिए अगर मैचिंग ग्रान्ट की कमी हो और उस हद तक पैसा नहीं हो तो आज विधायकों के क्षेत्र में ऐसी कोई स्कीम हो जिसमें केन्द्र सरकार का पैसा आया हो और मैचिंग ग्रान्ट देने की स्थिति में सरकार नहीं हो तो 10-20 लाख रुपये की आवश्यकता हो तो हमलोग जैसे आदमी विधायक कोष से मैचिंग ग्रान्ट देने के लिए तैयार हैं। बिहार सरकार के पास केन्द्र सरकार से पैसा आए तो वह पैसा वापस नहीं जाए मैचिंग के अभाव में।

एम0एल0ए0 लोगों के क्षेत्र का बहुत सारा रोड एन0एच0 में लिया गया जिसके लिए हम सिद्दिकी जी को, पथ निर्माण मंत्री थे अब नहीं हैं उनको केन्द्रीय मंत्री नीतिश जी को और हुकुमदेव बाबू को धन्यवाद देता हूँ। आजादी के 50 साल के बाद एन0डी0ए0 की सरकार ने बिहार में एन0एच0 में इन सारे रोड को लिया गया है। उत्तर बिहार के रोड को लिया गया है जिसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। कोई विकास तबतक नहीं होगा जबतक यातायात का विकास नहीं होगा। यदि गंगा का पुल नहीं बनता तो उत्तर बिहार के लोगों का विकास नहीं होता इसलिए हम चाहेंगे कि राज्य सरकार केन्द्र सरकार की जो भी योजना हो जिसमें जमीन की उपलब्धि नहीं हो उसमें जमीन उपलब्ध करावे और उसके पैसे को वापस नहीं जाने दें।

क्रमशः

से पैसा आया हुआ है जेल बनाने के लिए लेकिन उस पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा है, पैसे का बंदरबाट कर रहे हैं। जो भी केन्द्र से पैसा आता है उस पैसे के लिए अगर मैचिंग ग्रान्ट की कमी हो और उस हद तक पैसा नहीं हो तो आज विधायकों के क्षेत्र में ऐसी कोई स्कीम हो जिसमें केन्द्र सरकार का पैसा आया हो और मैचिंग ग्रान्ट देने की स्थिति में सरकार नहीं हो तो 10-20 लाख रूपये की आवश्यकता हो तो हमलोग जैसे आदमी विधायके कोष से मैचिंग ग्रान्ट देनेह के लिए तैयार हैं। बिहार सरकार के पास केन्द्र सरकार से पैसा आए तो वह पैसा वापस नहीं जाए मैचिंग के अभाव में। एन0एच0 में एम0एल0ए0 लोगों के क्षेत्र का बहुत सारा रोड लिया गया जिसके लिए हम सिधिकी जी को, पथ निर्माण मंत्री थे अब नहीं हैं उनको केन्द्रीय मंत्री नीतिश जी को और हुकुमदेव बाबू को धन्यवाद देता हूँ। आजादी के 50 साल के बाद एन0डी0ए0 की सरकार ने बिहार में एन0एच0 में इन सारे रोड को लिया गया है। उत्तर बिहा र के रोड को लिया गया है जिसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। कोई विकास तबतक नहीं होगा जबतक यातायात का विकास नहीं होगा। यदि गंगा का पुल नहीं बनता तो उत्तर बिहार के लोगों का विकास नहीं होता इसलिए हम चाहेंगें कि राज्य सरकार केन्द्र सरकार की जो भी योजना हो जिसमें जमीन की उपलब्धि नहीं हो उसमें जमीन उपलब्ध करावे और उसके पैसे को वापस नहीं जाने दें।

क्रमशः

श्री विजय कुमार मिश्र : क्रमशः सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि उड़िसा में जनता दल के श्री बीजू पटनायक मुख्यमंत्री थे । मैं भी जनता दल में था । उन्होंने उड़िसा में हजारों एकड़ जमीन एक्वायर करके छोड़ दिया कि केन्द्र सरकार की कोई योजना उड़िसा में बनेगी तो राज्य सरकार उसका उपयोग करेगी । मैं आग्रह करूंगा कि यह सरकार भी पटना से बाहर उत्तर बिहार में मुजफ्फरपुर, सहरसा, पूर्णिया आदि शहरों में जमीन एक्वायर करके छोड़ दे ताकि केन्द्र सरकार की कोई स्कीम बिहार के लिए बने तो जमीन को लेकर कोई विलंब न हो । राजगीर में आयुध का कारखाना बनने वाला है जमीन के लिए किसी वालों को जमीन के लिए इधर उधर घूमना पड़ रहा है । मेरा आग्रह होगा कि केन्द्र सरकार की कोई योजना कि सरकार इस बात को ध्यान में रखे कि केन्द्र सरकार की कोई योजना बिहार के लिए आये तो वह योजना पैसे के अभाव में या जमीन के अभाव में वापस न चली जाय । ऐसे विषय को राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखें । यह न सोचे कि यह नीतिश जी की दी हुई योजना है , यह वाजपेयी जी की दी हुई योजना है । राजनैतिक दृष्टिकोण से उसमें भी पक्षपात किया जाता है ऐसा अक्सर देखने में आता है । मुझे याद है 8-10 साल पहले औरंगाबाद में सुपर थर्मल पावर के लिए पैसा आया लेकिन आपसी राजनैतिक कारणों से वह आज तक नहीं बन सका । मैं कहूंगा कि केन्द्र सरकार की कोई योजना आये तो उसको कार्यरूप देने का काम करे । मोदी जी हैं, ~~xxxx~~ उमाशंकर बाबू हैं, कपिल बाबू हैं विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं उनका सहयोग चाहिए तो लें । मेरा कहना है कि केन्द्र सरकार की जो योजना आए उसको कार्यान्वित करने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर काम करे जिससे अधिक से अधिक लाभ बिहार सरकार को मिल सके । हम आपसे आग्रह करते हैं, मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं और कहना चाहते हैं कि इसमें सहयोग देने के लिए हम सब तैयार हैं ।

सभापति महोदय, मैं अब पटना शहर की गंदगी के बारे में बोलना चाहता हूँ । पटना शहर में नगर निगम कर्मियों के हड़ताल पर जाने के कारण शहर की स्थिति नारकीय हो गयी है । पटना शहर में कहीं भी जाते हैं तो भरी गंदगी भरी हुई है ! इस गंदगी को किसी तरह दूर करने की आवश्यकता है । पटना शहर बिहार की राजधानी है । इस

शहर की सफाई स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से या किसी और के माध्यम से भी हो सकती है । अगर काम करने में कठिनाई हो तो स्वयं सेवी संस्था का सहारा लिया जा सकता है । पटना की गंदगी से शहर की बदनामी होती है । पटना की गंदगी का मतलब है बिहार की बदनामी । जिले के विकास के लिए क्षेत्र के विकास के लिए विधायक फंड रहता है । अगर राज्य सरकार के पास पटना की सफाई के लिए पैसा न हो तो दो, चार, पांच लाख की आवश्यकता सफाई के लिए आवश्यक हो तो विधायकों से लेकर करायें । विधायक आवास जहां विधायक लोग रहते हैं वहां की गंदगी को दूर कराये ।

(व्यवधान)

श्रीमती राबड़ी देवी (मुख्यमंत्री) : मोदी जी, नवीन जी और नंद किशोर जी में से कोई अभी सदन में नहीं है । ये लोग पैसा देकर सफाई का काम करायें । पटना के सभी हैं ।

श्री विजय कुमार मिश्र: हम देने के लिए तैयार हैं । हम चाहेंगे कि पटना के विकास में हम सबों का सहयोग हो । पटना मोदी जी, नवीन जी और नंद किशोर जी का ही क्षेत्र नहीं है, सारे विधायक यहां रहते हैं इसलिए पटना की साफ सफाई में हम सभी सहयोग करें ।

(व्यवधान)

श्री रमई राम (मंत्री): आपको मालूम नहीं है सांसद, विधायक के फंड से भी बहुत सारा काम हुआ है ।

श्री विजय कुमार मिश्र: विकास तो हुआ है ही है । विकास नहीं ~~होता~~ हुआ होता तो बारह साल तक आप कैसे रहते ।

क्रमशः

श्री विजय कुमार मिश्रा:- बिहार की जनता विकास के कार्य को देखना चाहती है, इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह होगा कि आप पटना के विकास के लिए उसकी सफाई के लिए कार्य कीजिये, क्योंकि पटना बिहार की राजधानी है, यहाँ पर कोई खास दल या कोई खास लोग ही रहते हैं, इसलिए हम विकास नहीं करेंगे, इसतरह की भावना को नहीं लाना चाहिए और पटना को स्वच्छ बनाने के लिए सरकार हमलोगों से भी, अगर राशि चाहे, तो हम लोग भी देने के लिए तैयार है, इसमें हमलोग कोई कमी नहीं करेंगे, यह मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उमाशंकर सिंह:- सभापति महोदय, मंत्री लोग, बिना नियम कानून के कैसे खड़े हो जाते है, आसन से इसके लिए कोई नियमन नहीं होता है और मंत्री खड़े हो जाते है।

श्री रमई राम(मंत्री):- आपने किस नियम से बोल दिया, आपने जिस नियम से बोला, उसी नियम से तो हमको भी बोलने का अधिकार है।

(व्यवधान)

सभापति(श्री अनुप लाल यादव):- माननीय सदस्य, श्री यदुवंश कुमार यादव जी, आप अपना भाषण शुरू करें।

श्री यदुवंश कुमार यादव:- सभापति महोदय, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग एवं मंत्रिमंडल समन्वय विभाग का, जो बजट सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूँ। सभापति महोदय, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में, भारतीय प्रशासनिक सेवा, बिहार प्रशासनिक सेवा एवं न्यायिक सेवा, के स्थापन विषयक/पद प्रशासी विभाग है। इस विभाग के द्वारा सरकार ने अनेकों उपलब्धियाँ हासिल की है। इस विभाग का कार्य काफी सराहनीय एवं प्रशंसनीय रहा है, इसलिए मैं इस विभाग की मांग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सभापति महोदय, बिहार राज्य में, विगत पाँच वर्षों से, लोकायुक्त का पद रिक्त था, जिस पद को भरने का काम, हमारी सरकार ने किया है और एक अच्छे लोकायुक्त की नियुक्ति करने का काम विभाग ने किया है, जो कि प्रशंसनीय और सराहनीय काम है। इसके अलावे राज्य में हजारों मामलों

क्रमशः :

टर्न- 23/18.7.02,

सच्चिदा ।

श्री यदुवंश कुमार यादव : क्रमशः : हजारों मामलों में न्यायालय के अभाव में न्यायिक कार्य ठीक ढंग से, सुचारू रूप से नहीं हो पाता था, उसके लिए 183 ... फास्ट ट्रेक कोर्ट का गठन कर त्वरित न्याय देने की जो व्यवस्था की है, वह सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य है ।

महोदय, संयुक्त संवर्ग के 121 सहायकों को पदोन्नति देने का काम किया है । इसके अलावे राज्य पुनर्गठन के पश्चात जो सेवा संवर्ग का विभाजन का कार्य था, उसको पूरी मुस्तैदी से इस सरकार ने की है ।

: इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री भोला प्रसाद सिंह ने सभापति का आसन ग्रहण किया । :

परामर्शदातृ समिति कोसमय पर कागजात उपलब्ध कराने का का काम विभाग द्वारा बड़ी तत्परता से की गयी है । वर्ष 1978 में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जो परिपत्र, संकल्प, अनुदेश सरकार के स्तर से दी गयी थी, उन सारे परिपत्रों, संकल्पों को संकलित करके सभी माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराने का काम विभाग द्वारा किया गया है । महोदय, इसके अलावे तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति का भार बिहार लोक सेवा आयोग पर था, वह भार लोक सेवा आयोग से बिहार अवर सेवा चयन आयोग की स्थापना करके उसको दे दी है । यह एक प्रशंसनीय और सराहनीय कार्य किया गया है ।

सर्वोच्च न्यायालय के निदेश पर महिला उत्पीड़न कानून में सुधार लाकर और समीक्षात्मक निवारण समिति की स्थापना करके विभाग ने महिलाओं के कल्याण के लिए बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य किया है । इतना ही नहीं 14 वर्ष के बच्चे जो किसी कार्य में लगे हुए हैं, पर प्रतिबंध लगाने का काम सरकार ने की है । विभाग ने बिहार सरकारी सेवक नियमावली में सुधार करने का काम बड़ी मुस्तैदी से किया है । इसके अलावे राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारियों की सीधी भर्ती की जो अवधि वर्ष 2000 तक थी, उसको बढ़ाकर वर्ष 2005 तक करने का काम किया गया है । इस विभाग द्वारा सभी विभागों को सम्यक रूप से कार्य करने का प्रावधान किया है और मुझे विश्वास है कि माननीया मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में यह विभाग अच्छा काम करेगा । इस विभाग के माध्यम से आनेवाले समय में सारे विकास कार्य और प्रशासी संबंधी कार्य बड़ी तेजी और त्वरित गति से होता रहेगा ।

सच्चिदा ।

सभापति : श्री भोला प्रसाद सिंह : माननीय सदस्य श्री उमा शंकर जी आसन आपको रू-ब-रू देखना चाहता है ।

श्री यदुवंश कुमार यादव: महोदय, हम एक सुझाव देना चाहते हैं । बहुत से माननीय सदस्यों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी का पद भरे जाने के संबंध में चर्चा की है । बिहार लोक सेवा आयोग से काफी संख्या में प्रखंड विकास पदाधिकारी का पद भरे जाने की कार्रवाई की गयी है । साथ ही अंचलाधिकारी का पद भरने की कार्रवाई सरकार कर रही है । (क्रमशः)

श्री यदुवंश कुमार यादव (क्रमशः):- (व्यवधान)

महोदय, नये प्रखंड एवं नये अनुमंडल की स्थापना की गई है। गांव के दबे कुचले लोग पहले प्रखंड मुख्यालय नहीं जाते थे, सरकार ने नये प्रखंडों की स्थापना करके वास्तव में आम लोगों को वहां पहुंचाने का काम किया है। लेकिन इसमें कुछ त्रुटियां रह गई है जिसमें सुधार की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि नये प्रखंड की स्थापना हुई, नये अनुमंडल की स्थापना हुई लेकिन प्रखंड में जो अन्य सारे विभाग है, जैसे शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग या अन्य विभाग हैं उनको उस नये प्रखंड या अनुमंडल के आधार पर उसमें जोड़ने का काम नहीं हुआ है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां जो प्रखंड जिस रूप में स्थापित किया गया है, उसी रूप में अन्य विभागों को भी उस प्रखंड या मुख्यालय में जोड़ने का काम किया जाये। उदाहरणस्वरूप, मेरे यहां मरचा-गाड़ भपटिहा प्रखंड की स्थापना की गई। लेकिन निर्मली प्रखंड में आनेवाले 9 पंचायत हैं उनका अनुमंडल, न्यायिक कार्यालय वीरपुर में है। उसी प्रकार किशनपुर का पंचायत का हाल है। अनुमंडल और न्यायिक कार्यालय सुपौल में है। इससे वहां की जनता को काफी परेशानी हो रही है। अतः मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जहां जो प्रखंड जिस रूप में स्थापित किया गया है, उस रूप में जनता की सुविधाओं का ख्याल करते हुए वहां अनुमंडल कार्यालय और न्यायिक कार्यालय की स्थापना की जाये। उसी तरह से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की भी वही स्थिति है। उसमें भी सुधार लाने की आवश्यकता है। साथ ही, थानों की सीमा में भी सुधार लाने की जरूरत है। इस प्रकार किस आधार पर जहां पर प्रखंड की स्थापना की

गई है, : : उसी आधार पर सारे विभागों को जोड़ने का कार्य किया जाये।

आमलोगों की असुविधा को ध्यान में रख कर जिस उद्देश्य से प्रखंड एवं अनुमंडल की स्थापना की गई है उनमें उसी अनुरूप सुधार भी होना चाहिए। ताकि आमलोग सुगमता से अपने मामले को वहाँ ले जाने का काम कर सकें। महोदय, सरकार की जो उपलब्धि रही है, विपक्ष के लोग उसे उठाने का काम नहीं करते हैं। यह ठीक है कि सरकार के जो कमजोर पक्ष होते हैं, उसको उठाने की आवश्यकता हो सकती है लेकिन सरकार के अच्छे कार्यों की भी सराहना करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं करके विपक्ष के लोग हर मामले को एक ही तराजू में तौलने और आंकने का काम करते हैं। यह उचित नहीं है। महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा गांव के दबे कुचले, दलित, पिछड़े तमाम लोगों के हित और उसके हक की बात की जाती है, सारे विकास कार्य पंचायत के माध्यम से किये जाते हैं। यह निश्चित रूप से सरकार की उपलब्धि है और सरकार की इच्छाशक्ति की देन है जिस के विषय पर भारत सरकार द्वारा जिस तरह से सरकारी राशि को रोक कर विकास के कार्यों को रोककर रखने का काम किया क्योंकि उन्हें ऐसी आशंका थी कि बिहार में कभी पंचायत का चुनाव नहीं होगा।

(क्रमशः)

श्री यदुवंश कुमार यादव : क्रमशः - लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने अपने कुशल नेतृत्व, अपने मजबूत इच्छाशक्ति के बल पर बिहार में पंचायतों का चुनाव कराकर सारे पंचायतों को अधिकार देकर, पंचायत को अधिकार दे/लैश किया है। पंचायत का जो छठा खम्भा की परिकल्पना थी और ग्राम पंचायत को जो अधिकार देने की परिकल्पना थी उन सारे इच्छा और कल्पनाओं की पूर्ति करने का काम किया है जो कि एक सराहनीय और प्रशंसनीय कदम है। इस प्रशंसनीय कदम और सराहनीय कदम की प्रशंसा करते हुये आज जो माँग प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करते हुये मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री भोला प्रसाद सिंह) : शांति-शांति। माननीय सदस्य, श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल।

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : सभापति महोदय, आज जिस गम्भीर विषय पर इस सदन में वाद-विवाद और चर्चा कर रहे हैं, निश्चित रूपसे बिहार का विकास ऐसे जो गम्भीर विषय हैं, इनपर टिका हुआ है। आज कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, संसदीय कार्य विभाग, मंत्रिमंडल समन्वयन विभाग और अन्य जो विषय आये हैं, निश्चित रूपसे इनको विकास का आधार माना जाता है।

महोदय, अगर/हमलोग नगर की बात करें तो चिड़ैयाटाड़ पुल से लेकर सीधे पूरब की तरफ जायें, जो सड़क पूरब की तरफ जाती है, उस सड़क के दोनों तरफ अगर हम ध्यान दें तो आज लगता है कि सड़क का इनक्रोचमेंट हो गया है और यह इनक्रोचमेंट सिर्फ गंदगी, पानी और कीचड़ किये हुये हैं। बड़े पैमाने पर यहाँ से लेकर गाँधी सेतू के नीचे तक दोनों साईड में पानी एवं कीचड़ लगा हुआ है। गाड़ियों पर आने-जाने में अगर आप जाम में फँस गये तो घंटों लग जाता है। यह तो नगर विकास विभाग की स्थिति है। चाहे यह तिवारी पेचर हो या उससे आगे, यह स्थिति बनी

हुई है । हम सारे माननीय सदस्य, सारे माननीय मंत्रीगण उस सड़क से आने-जाने का काम करते हैं लेकिन हम ध्यान नहीं दे रहे हैं ।

महोदय, विधायक क्लबों और फ्लैटों की जो स्थिति है, उनके इर्द-गिर्द जो कचड़ा पड़ा हुआ है, हमें लगता है कि कभी-भी कोई संक्रामक बीमारी हो सकती है, इससे इनकार हम नहीं कर सकते हैं । भले ही कुछ हमारे माननीय मंत्री और माननीय सदस्य अच्छे बंगले में रहते हों, उनके यहाँ दिन भर में तीन चार सफाई होती हो, कीटनाशक दवाईयों का छिड़काव होता हो लेकिन अन्य जो हमारे माननीय सदस्यगण जहाँ रहते हैं, वहाँ पानी, बिजली और सफाई की जो व्यवस्था है, निश्चित रूपसे हम सभी को उसपर ध्यान देने की जरूरत है और यह पूरे इस सदन के लिये एक सोचनीय विषय है।(क्रमश:)-

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : महोदय, यह सदन के लिए सोचनीय है। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आंकड़ों एवं राज्य के अन्य जिलों की ओर न ले जाते हुए मैं अपने जिले की ओर ले जाना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि आज राजनैतिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग पर हम चर्चा कर रहे हैं, सारण जिला में नवम्बर, 2011 से डी०डी०सी० का पद रिक्त है। हमारे साथ माननीय मंत्रिगण बैठे हुए हैं और नवम्बर 2011 से यह पद रिक्त है। विकास करने का दायित्व सरकार डी०डी०सी० के ऊपर दी है और सबका एक साथ बोलते जो है और डी०डी०सी० नहीं है, अंचलों में अंचलाधिकारी नहीं हैं, प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारी नहीं हैं, 130 मेलजमा पंचायत सेवकों के पद रिक्त हैं, आप कैसे विकास करेंगे? आप विकास की बात करते हैं और इतने पद आज रिक्त हैं। आप कैसे विकास कर पायेंगे? आप विकास नहीं कर सकेंगे।

महोदय, अब मैं उद्योग की बात कहना चाहता हूँ। अब मैं सुनता था तो मढ़ौरा का मार्टन चौकलेट और उसकी अच्छी क्वालिटी के चीनी की चर्चा सुनते थे लेकिन महोदय जब से यह सरकार बनी है, 90 के बाद से तो न वह चौकलेट दिखायी दे रहा है और न वह सर्वश्रेष्ठ चीनी दिखायी दे रहा है। महोदय, सारण इंजीनियरिंग डिस्टिलरी और दूध उत्पादन करनेवाले जो दूध उत्पादित करते थे, जो वहाँ पर उद्योग था वहाँ पर वे दूध देते थे, गन्ना उत्पादन करनेवाले किसान अपना गन्ना चीनी मिल में देते थे, इन सब उद्योगों के बंद हो जाने के कारण आज सारे लोग बेकार पड़े हुए हैं। हजारों की संख्या में बेरोजगार आज भूखमरी के कगार पर हैं। महोदय, यह स्थिति है।

होदय, सड़क की स्थिति के संबंध में, मैं अपने क्षेत्र का शून्य-काल में माननीय मंत्रीजी का ध्यान दिलाया था, कुछ सड़क है छपरा से मरौढ़ा जानेवाली....

(व्यवधान)

सड़क के लिए सरकार ने आश्वासन भी दिया था लेकिन आज वहाँ सड़क नहीं है सड़क आज नाले बन गये हैं।

सभापति (श्री भोला प्रसाद सिंह): माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें।

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : महोदय, एक मिनट। वहाँ नाले बन गये हैं, कृष्णा मोड़ से लेकर खैरा बाजार जो छपरा जिला के नगरा प्रखंड में है। आपने इसके संबंध में आश्वासन भी दिया था। एक पखवारे लगभग हो गये लेकिन आप ध्यान भी नहीं देते। यह आज मंत्रियों की सफलता है।

महोदय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय की स्थापना 1952 में की गयी, पैसे भी दिये गये लेकिन आजतक भवन का निर्माण नहीं हो सका जिसके कारण पढ़ाई भी बाधित हो रही है।

सभापति (श्री भोला प्रसाद सिंह): अब आप समाप्त करें।

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : सभापति महोदय, मैं मानता हूँ कि आज सिर्फ मंत्रियों के लिए मोटर, हीटर, लोटर और सीटर के अलावे के लिए कोई अन्य व्यवस्था नहीं है, मैं इसपर विशेष चर्चा नहीं करना चाहता हूँ।

...क्रमशः...

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : (क्रमश:) लेकिन इसके अलावा मंत्री को कुछ नहीं चाहिए और न वे लेने के लिए तैयार हैं । आपने मुझको जो समय दिया और मैंने अपनी बात रखी, इसके लिए आपके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ ।

श्री सुशील कुमार मोदी (नेता विरोधी दल) : सभापति महोदय, मैं सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूँ कि पशुपालन विभाग बिहार में बन्द कर दिया जाय । क्योंकि इस विभाग के जो भी मंत्री बने हैं, वे जेल चले गये हैं । भोला राम तूफानी मंत्री बने, वे जेल चले गये, श्री चन्द्रदेव प्र०वर्मा मंत्री बने, वे जेल चले गये, श्री विद्यासागर निषाद मंत्री बने, वे जेल चले गये, श्री आदित्य सिंह मंत्री बने, वे जेल चले गये, श्री रामाश्रय सहनी मंत्री बने, वे भी जेल चले गये हैं । इसलिए जिनको चार्ज दिया गया है, कहीं वे भी न जेल चले जायें । इसलिए इस पशुपालन विभाग को बन्द कर दिया जाय ।

सभापति (श्री भोला प्र०सिंह) : माननीय नेता विरोधी दल, जेल वे जा रहे हैं और चिन्ता आपको क्यों हो रही है ?

(व्यवधान)

शांति-शांति । माननीय सदस्य श्री प्रहलाद यादव ।

श्री प्रहलाद यादव : सभापति महोदय, आज का जो विषय है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है । मंत्रिमंडल,सचिवालय एवं समन्वय विभाग पर दो दिन से चर्चा चल रही है और मैं मांग के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में । सभापति महोदय, किसी भी प्रदेश का मंत्रिमंडल सचिवालय और समन्वय वह हृदय होता है, वह विभाग जितना मजबूत होगा, उतना ही राज्य भी मजबूत होगा ।

सभापति (श्री भोला प्र०सिंह) : शांति-शांति । गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है और माननीय मंत्रीगण इस गंभीरता को महसूस करें ।

श्री नवीन किशोर प्र०सिन्हा : सभापति महोदय,.....

सभापति(श्री भोला प्र0सिंह): मैं जानता हूं कि आप सदन को गंभीर होने नहीं देंगे ।

श्री प्रहलाद यादव : सभापति महोदय, सरकार का जो कार्यक्रम है, वह कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय है । जिसके कारण लम्बे अरसे से यह सरकार स्थायी है । अगर सरकार का कार्यक्रम सही नहीं होता तो निश्चित रूप से जनता उस सरकार को, उस पार्टी को नकार देती, यह यह साबित करता है कि सरकार का जो कार्यक्रम है, वह सराहनीय है और यह प्रदेश के लिए अच्छा है ।

सभापति महोदय, जहां तक विधि-व्यवस्था का सवाल है, इसके संबंध में कहना चाहता हूं, यहां के विधिव्यवस्था के बारे में विपक्ष के लोग जितना निन्दा करते हैं, वे अगर अन्दर से झांक कर देखें तो इसके लिए वे लोग भी दोषी होंगे । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र के लखीसराय के सूर्यगढ़ा थाना में 2 महिला के साथ बलात्कार किया गया, उस पर दबाव दिया गया और इसके पैरवीकार माननीय विरोधी दल के नेता थे, आखिर बताईए कैसे विधि-व्यवस्था सुधरेगा, यह स्थिति है । बालू घाट के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं....

सभापति(श्री भोला प्र0सिंह): माननीय सदस्य, बैठे-बैठे जो बात कही जा रही है, वह सदन का हिस्सा नहीं है ।

श्री प्रहलाद यादव : सभापति महोदय, कहा जाता है कि व्यापारी भाग रहे हैं । आखिर पुलिस कोई भगवान नहीं है। जब तक उनके पास रिपोर्ट नहीं आता है, उस पर वे कार्रवाई कैसे करेंगे ? चुपके से जो भाग रहे हैं, उसकी जिम्मेवारी नहीं है....

(क्रमशः)

टर्न-28-18-7-2002/मुस्ताक

श्री प्रह्लाद यादव(क्रमशः):- इसलिए जितनी भी घटनायें घटी हैं ,ऐसी बात नहीं है कि ,एफ0 आई0 आर0 हुआ ,उसे देखा गया ,निश्चित रूप से देखा गया ,उसमें कार्रवाई हुई और उसमें एक्शन हुआ ,ऐसी बात नहीं है कि एकतरफा दोषारोपन करने से काम नहीं चलने वाला है ,बिहार की उन्नति चाहते हैं, बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को सोचना पड़ेगा ,कौन दोषी है और कौन नहीं है ,इसका राजनीतिक लाभ के लिए अगर इस तरह का बावेला मचता है ,एक दूसरे पर दोषारोपन करके राजनीतिक लाभ लेने की बात होगी तो निश्चित रूप से प्रदेश नहीं बन सकता है ,देश नहीं बन सकता है ,इसलिए राजनीतिक लाभ लेना बंद कीजिए और जनता के हित में ,जनता के पक्ष में सोचिये अगर नहीं सोचते हैं तो इस पर विचार नहीं करते हैं तो निश्चित रूप में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं । माननीय सदस्य जानते हैं कि इससे जनता का कल्याण नहीं होगा ,देश का विकास नहीं होगा कश्मीर को तीन भागों में बांट देने से जनता को कोई फायदा नहीं होगा,मन्दिर के निर्माण करने से जनता का कल्याण नहीं होगा , यह सब एक राजनीतिक हथकंडा है इस राजनीतिक हथकंडा को अपनाकर सत्ता मिले और हमारे पार्टी आगे बढ़े । इस तरह से काम नहीं चलेगा । महोदय जब तक सबों का को-आर्डिनेशन नहीं होगा ,सभी का एक तरह से कनेक्शन नहीं होगा ,पदाधिकारी कुछ करते हैं और हमलोग अगर दूसरे रास्ते पर चले तो निश्चित रूप से आगे नहीं बढ़ सकते हैं । जो पदाधिकारी हैं वे टाईम पर कार्यालय आयें हमलोग जो जनता का काम करवाते हैं , एक एक संचिका 15 दिनों तक और एक महीना तक रखा दिया जायेगा तो उसका क्या होगा ।

सभापति (श्री भोला प्रसाद सिंह):- 4-30 को सरकार का जवाब होगा और 4-55 पर माननीय मुख्य मंत्री सदन में कोई महत्वपूर्ण घोषणा करेंगी ।

श्री प्रह्लाद यादव :- सभापति , महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को एक सूचना देना चाहता हूं कि मैट्रिक बोर्ड का जो परीक्षा हुआ ,उसमें हजारों लड़कों का

रिजल्ट रुका हुआ है, किसलिए रुका हुआ है, ज्यादा रूज के चलते रुका हुआ है। मैं इस संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव से मिला था उनसे कहा कि जिस समय रजिस्ट्रेशन हो रहा था, जिस समय फॉर्म भारा जा रहा था उसी समय क्यों नहीं रोक दिया गया, अब रिजल्ट हो गया तो क्यों रोका जा रहा है ? मैं सरकार को सलाह दूंगा कि यह हजारों लड़कों के लाइफ का सवाल है, रिजल्ट खाराब हो गया तो उसके चलते कहीं एडमीशन नहीं होगा, सर्विस नहीं होगा। इसलिए इस तरह की बात पर सरकार ध्यान दे।

क्रमशः

क्रमशः

श्री प्रहलाद यादव : जब हमलोग किसी पदाधिकारी के पास समस्या लेकर जाते हैं मिलने के लिए तो कहा जाता है कि वे मीटिंग में हैं । ये लोग हमेशा मीटिंग में ही रहते हैं । इसतरह से किसी को घुमाना नहीं चाहिए । सभापति महोदय, इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए । कोई योजना हो ,प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना हो, एम0आर0 की कोई योजना हो उन सब का कार्यान्वयन समय पर नहीं हो रहा है । सरकार को निश्चित रूप से इनके कार्यान्वयन पर ध्यानदेना चाहिए । जो प्रक्रिया है उसको जबतक पूरा नहीं किया जायेगा तबतक कोई काम पूरा नहीं किया जासकता है लेकिन इन कामों को करने में विलम्ब किया जाता है इसके लिए पदाधिकारियों पर अंकुश लगाया जाना चाहिए तब ही बिहार आगे बढ़ सकता है जो विपक्ष के लोग हैं वे सरकार के अच्छे कामों को नहीं बताकर बल्कि सरकार को निकम्मी और कला चिल्ला कहकर अपनी बात यहाँ रखते हैं । कम से कम इतना जरूर होना चाहिए कि सरकार के अच्छे कामों को यहाँ बताना चाहिए । लालबत्ती जल गई है इसलिए हम अपनी बात समाप्त करते हैं ।

श्री राम स्वार्थ राय :सभापति महोदय, आज मंत्रिमंडल समन्वय विभाग की माँग पर सदन में बहस हो रही है । मंत्रिमंडल समन्वय , बिहार सरकार की उपलब्धियाँ ,राजनीतिक दल ,राजनीतिक दल के कार्यक्रम और इसकी जो व्यापकता है उसके बारे में घंटों तक सदन में बहुत बताया जाय वह कम ही होगा । दो तीन मुद्दों पर सरकार की उपलब्धियों को रखते हुए चाहूँगा कि सदन इससे सहमत हो कि सबसे बड़ी बात यह है कि 12 वर्षों के शासन में बिहार सरकार ने लगातार भारतीय संविधान के उन प्रीएम्बुल के मुताबिक सामाजिक ,आर्थिक ,सांस्कृतिक ,राजनीतिक विकास के कार्यक्रम में जो काम किए हैं निश्चित रूप से वैसे लोग जो पूँजीपति और सामन्तों के पक्षधर हैं जो बदलाव के विरोधी है उनको इस सरकार के कार्यकलाप अच्छे नहीं लगते लेकिन बात समझ में नहीं आती है कि समता पार्टी के लोग और जनता दल यू के लोग जो समाजवादी चिन्तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के औलाद कहे जाने वाले लोग जो राजनीतिक दल का दृष्टिकोण होता है उस

दृष्टिकोण के मुताबिक कार्यक्रमों का समर्थन करना और विरोध करना स्वाभाविक है । जब गणेश बाबू अपनी बात रखते हैं तो एक बात समझ में नहीं आती कि भोला बाबू ने कहा कि बिगड़े हुए जमींदारों के कब्र पर उपजी हुई घास बहुत जहरीली होती है तो स्वाभाविक है । जब उनकी संगति हो गई बी0जे0पी0 वालों से जब संगति हो गयी ,आर0एस0एस0 के लोगों से तो कैसे बुझियेगा उस गरीब को जो सीना चौड़ा कर मांगता है मजदूरी 59 रूपया और 60 रूपया । इनकी तो आदत थी मंगनी में खटाने का ,इनकी आदत थी दास्ता और गुलामी को स्वीकार कराने का लेकिन 12 वर्षों के शासन काल में गरीबों के अंदर जो गुलामी थी जो सामन्तों की पकड़ थी उसका मुकाबला करने का काम किया है । मतलब यह है कि ....

सभापति (श्री भोला प्रसाद सिंह): शांति, शांति, रामस्वार्थ बाबू आप आसन की तरफ मुखातिब होकर बोलिये, श्री गणेश प्रसाद यादव की तरफ मुखातिब नहीं हो क्योंकि ये भी खड़ा होने की तैयारी कर रहे हैं ।

श्री गणेश प्रसाद यादव: महोदय, इनका दर्द है पुराना ।

सभापति (श्री भोला प्रसाद सिंह): श्री गणेश प्रसाद यादव उनका दर्द पुराना है और आपका नया ?

श्री गणेश प्रसाद यादव: ये जो कह रहे हैं इनका दर्द पुराना है और अब ये हो गए हैं नवोदित सामन्त और ये बोलेरो से नीचे नहीं चलते हैं ।

श्री राम स्वार्थ राय: महोदय, प्रसन्नता की बात है । जब गरीब के बेटा में ताकत आती है तो स्वाभाविक रूप से आज हमारे समाज में जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उसमें सामन्त और बड़ी ताकते भी कहती हैं बहुत बहादुर है तो स्वाभाविक है हम गरीब के बेटे को सामन्त और गणेश बाबू ने अपने भी स्वीकार कर लिया है जिसको बोलेरो और सीरी चीजें दे दिया है तो बचा क्या है इसलिए महोदय ,यह सरकार की उपलब्धि है ।

सभापति (श्री भोला प्रसाद सिंह): श्री राम स्वार्थ राय जी यह तो उनकी कृपा हुई, उनका आदर्श हुआ लेकिन आप अपनी निगाह भी ठीक रखें ।

[illegible]

[illegible]

सभापति (श्री भोला प्रसाद सिंह): अब आप प्रशासन पर बोलिये ।

श्री राम स्वार्थ राय: सभापति महोदय, ये लोग कैबिनेट कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे थे । बात समझ में नहीं आ रही है । राष्ट्रीय जनता दल की सरकार की नीति और कार्यक्रम है । जनता दल यू की क्या नीति और कार्यक्रम है इसके बारे में गणेश बाबू को जो उस दल के नेता है उनके दिल में के अंदर जो दल की नीतियाँ है उसके बारे में ये सदन में प्रकाश डालते तो बात समझ में आ सकती थी । जनता दल यू के लोग वास्तव में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता चाहते हैं या साम्प्रदायिकता और पूंजीवाद यह स्पष्ट करना चाहिए था लेकिन उसको स्पष्ट नहीं करके इतनी ओछी बात सरकार के अंदर जो काम करते हैं उनके बारे में उनहोंने चर्चा की । जो काम करता है काम करने में गलती उसी से होती है लेकिन जो काम ही नहीं करते हैं उनसे क्या गलती होगी । ये विपक्ष के लोग हैं ये सरकार की उपलब्धियों से घबराते हैं ।

क्रमशः

श्री रामस्वार्थ राय: प्रयास: सरकार की बड़ी उपलब्धि है । अरबों खर्च करके बिहार की 80 प्रतिशत आबादी का जो मनोबल ऊंचा हुआ है उसके पॉकेट में जो पैसा गया है, आज उसके बदन पर अच्छा कपड़ा है, रहने के लिए पक्का मकान है , गिट्टी और मिट्टी का दाम पूछता हैं तो इनको जलन होती है । इनकी दृष्टि गांवों के गरीबों की ओर पहले नहीं थी । गणेश जी है जैसे लोग जो डा० राम मनोहर लोहिया के ..र औलाद कहे जाते हैं उनके संबंध में निश्चित रूप से एक बात कहना चाहता हूं कि सत्ता का जो सर्वोच्च स्थान केन्द्र की जो सत्ता है और जो उसकी शक्ति है उसके सामने बिहार की शक्ति कैसे बढ़ेगी क्योंकि आज गुजरात की शक्ति बढ़ रही है, बंगाल की शक्ति बढ़ रही है , यू०पी० की शक्ति बढ़ रही है और जो केन्द्र से धाराएं चलती है वह इन राज्यों तक पहुंच रही है लेकिन गणेश बाबू बिहार वासी होते हुए बिहार के प्रति आपको दर्द होता तो निश्चित रूप से जो केन्द्र का पक्षपात है, जो बेईमानी है जो गाडगिल फार्मूले से बाहर जाकर आवंटन होता है, बिहार का जो अंश होना चाहिए वह केन्द्र सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है और यह केन्द्र सरकार की यह तमन्ना बिहार की सरकार को नीचे दिखाने के लिए होती है । सभापति जी हम कहना चाहते हैं कि विपक्ष के लिए संभव है कि बिहार सरकार अच्छी नहीं हो लेकिन बिहार के वासियों के लिए बिहार का विकास सर्वोपरि है । विपक्ष में बैठे हुए लोग सरकार की इन खामियों को बताते हुए केन्द्र के पक्षपात और केन्द्र की बेईमानी और गाडगिल फार्मूले के मुताबिक योजना का निरूपण नहीं होना यह इतनी बड़ी बेईमानी है और बिहार के साथ विश्वासघात है , बिहार के साथ इतनी बड़ी दगाबाजी है जिसका वर्णन जितना किया जाय महोदय कम है इसलिए मैं खासकर विपक्ष के नेता जिनकी बात कभी कभी मैं सुनता हूं बहुत अच्छी बात कहते हैं जब उस बेंच पर होते हैं लेकिन सभापति महोदय ,आपकी बात और अच्छी लगती है लेकिन समाजवादी, साम्यवादी दलों में होने के कारण जो

आपके अंदर चिन्ता और चिन्तन [illegible] [illegible] हों [illegible] रूप से सरकार और विपक्ष दोनों के लिए मार्गदर्शन का काम करता है।

क्रमशः

टर्न-31/राजेश/18.7.2002

श्री रामस्वार्थ राय(क्रमशः):- जिसतरह से हमलोग विपक्ष की बातों को सुनते हैं, मुझे खुशी होती जब हमारी बातों को भी विपक्षी साथी, पूरे ध्यान के साथ सुनते और उसपर अमल करते, तो मैं समझता हूँ कि अपराधियों को संरक्षण देने का काम और सरकार पर तोहमत लगाने का काम शायद आपलोग नहीं करते । इसलिए आज सचमुच में ......

सभापति(श्री भोला प्रसाद सिंह):- अब आप समाप्त करें ।

श्री रामस्वार्थ राय:- सभापति महोदय, आज जो घोटाला करने वाले लोग है, आज जो घोटाला करने वाली पार्टी है, वही पार्टी हमलोग पर उंगली उठाती है कि हमारी सरकार घोटाला की सरकार है, जबकि उन्हें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि इस देश में केन्द्र की सरकार के द्वारा यू0टी0आई0का भयंकर घोटाला हुआ, लेकिन इनलोगों के मुँह से आवाज तक नहीं निकला और उलटे इन्हीं लोगों के द्वारा, हमारी सरकार को बदनाम किया जाता है कि हमारी सरकार घोटाले बाजों की सरकार है, इस सरकार में सिर्फ घोटाला ही घोटाला होता है । इसलिए मेरा आपके माध्यम से आग्रह होगा कि इस सदन में, जब भी कोई माननीय सदस्य कुछ बोले तो इस बात का अवश्य ख्याल रखना चाहिए और खासकरके हमारे विपक्षी साथियों से मैं यह कहना चाहूँगा कि वे जो भी बोले, पूरी जिम्मेवारी के साथ बोले । सभापति महोदय, ऐसा लगता है.......

सभापति(श्री भोला प्रसाद सिंह):- अब आप समाप्त करें ।

(व्यवधान)

श्री रामस्वार्थ राय:- सभापति महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि जब इधर के माननीय सदस्य बोलते हैं, तो माननीय सदस्य श्री गणेश बाबू भी बोलने लगते हैं, लगता कि जैसे ये दोनों जुड़वा भाई हो, हमेशा उनके द्वारा इस ओर के माननीय सदस्य को डिसटर्ब किया जाता है.......

(व्यवधान)

सभापति(श्री भोला प्रसाद सिंह):- माननीय सदस्य, अब आप बैठिये । अब सरकार का जवाब होगा ।

श्री रामस्वार्थ राय:- सभापति महोदय, आज हमारी सरकार ने, जिसतरह से सत्ता का विकेन्द्रीकरण एवं इसको संवेदनशील बनाने का काम किया है और इसी विकेन्द्रीकरण एवं संवेदनशीलता के लिए हमारी सरकार ने, गरीबों को लाभ पहुँचाने के लिए, नये-नये जिलों का, नये-नये अनुमंडलों का, नये-नये प्रखंडों का सृजन किया । सभापति महोदय, मैंने अपने भाषण के क्रम में, सरकार की उपलब्धियों का, जो बयान किया है, वह शायद माननीय सदस्य श्री गणेश बाबू को बुरा लगेगा, लेकिन अगर इनके सीने में जरा भी गरीबों के प्रति दर्द है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बातों से इनके दिल में, जो गरीबों के प्रति दर्द है, वह बुझेगा । इन्हीं

शब्दों के साथ सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति (श्री भोला प्रसाद सिंह):- अब सरकार का जवाब होगा ।

सरकार का जवाब
===============

श्री रामचन्द्र पूर्वे (मंत्री):- सभापति महोदय, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अनुदान पर, दो दिनों के वाद-विवाद में, माननीय सदस्यों ने, हिस्सा लेकर बहस को सार्थक और सगुण बनाया है, इसके लिए मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ । महोदय, बहस के क्रम में, माननीय सदस्यों के द्वारा जो बहुमूल्य सुझाव दिये गये हैं, उनको कार्यरूप देने पर सरकार विचार करेगी ।

सभापति महोदय, संसदीय लोकतंत्र में, इस सदन की व्यवस्था और सदन की कार्यवाही का बहुत ही महत्व है । आज सदन की कार्यवाही का 18वाँ दिन है और इस अवधि में माननीय सदस्यों के द्वारा, जो प्रश्न पूछे गये हैं, जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आये और बहस के दौरान जो बातें कही गयी, वह हमारे माननीया मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में

क्रमशः